

कुंडुख टाइम्स

(अंक 11, अप्रैल - जून)



Prepared by:

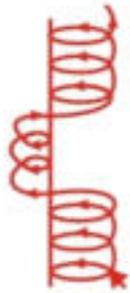
Addi Kurukh Chaala Dhumkuniya
Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi

Published by:

Tribal Cultural Society, Jamshedpur
An Ethnicity wing of TATA STEEL FOUNDATION

Tata Steel Foundation (Foundation), a wholly owned subsidiary of Tata Steel Limited, was incorporated on August 16, 2016. With over 600 members spread across eleven units and two states of Jharkhand and Odisha, the Foundation is a CSR implementing organisation focused upon co-creating solutions, with tribal and excluded communities, to address their development challenges reaching more than 1.5 million lives annually across 4,500 villages. The Foundation endeavors to implement change models that are replicable at a national scale, enabling significant and lasting betterment of communities proximate to Tata Steel's operating locations while embedding a societal perspective in key business decisions. The Foundation strives for excellence by ensuring that all programmes are aligned with community needs and focused upon national priority areas enabling communities to access and control resources to improve the quality of their lives with dignity.

तोलोड सिकि (लिपि) का आधार



तोलोड पोशाक



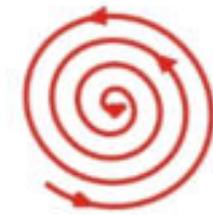
हल-बलाना



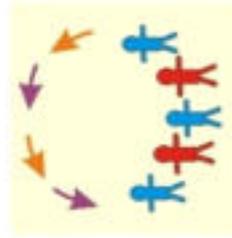
बाला अयंग अड्डा



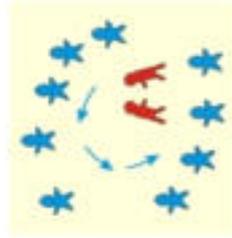
जता चलाना



रोटी पकाना



नृत्य



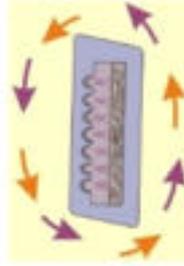
अभिवादन



जीव-जन्तुओं द्वारा बनाये गये चिन्ह



मृदु संस्कार



देवी अयंग अड्डा



पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा



लत्तर का डाली पर चढ़ना



सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चिन्ह



चिन्बु लिपि (Indus Script)



उष्ण कट्टा किससे मिलान

तोलोड सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, शीतिरिवाज, परम्परा, विज्ञान एवं आध्यात्म का अद्भूत प्रस्तुतिकरण

4. छिन्न भिन्न होती आदिवासियत

– भुनेश्वर बखला

“आदिवासियत” शब्द का मतलब आदिवासी जीवनशैली, संस्कृति, परंपराओं, और जीवन मूल्यों से है जिसे आदिवासी समुदाय अपने आत्मीयता में संरक्षित रखते हैं। यह उन समुदायों की पहचान और धरोहर को संदर्भित करता है जो प्राचीन काल से अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार आदिवासियत को निम्नलिखित बिन्दुओं से परिभाषित कर सकते हैं –

1. सांस्कृतिक धरोहर – आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर में उनके रिवाज, त्योहार, पारंपरिक नृत्य, संगीत, और कला शामिल हैं। यह धरोहर उनके धार्मिक विश्वासों, मिथकों, और पारम्परिक ज्ञान में भी परिलक्षित होती है।

2. भाषा और साहित्य – आदिवासी भाषाएँ और साहित्य उनकी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह भाषाएँ और बोली अलग-अलग समुदायों में विविधता लिए हुए हैं। भाषा उनकी विशेष पहचान और समृद्धता का स्रोत होती है।

3. पारम्परिक ज्ञान और प्रथाएँ – आदिवासियों के पास पर्यावरण, चिकित्सा, कृषि, और वनोपज के क्षेत्र में समृद्ध पारम्परिक ज्ञान होता है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया जाता है। यह ज्ञान उनकी आजीविका और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है।

4. सामाजिक संरचना – आदिवासी समाज में सामाजिक संरचनाएँ आमतौर पर सामूहिकता, समानता और सहभागिता पर आधारित होती हैं। इनके समाज में समुदाय की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। आदिवासी समुदाय अक्सर अपनी आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते हैं और समुदायी उत्पादन, जैसे कि खेती, शिकार और पशुपालन पर निर्भर करते हैं।

5. पर्यावरणीय जुड़ाव – आदिवासी लोग आमतौर पर प्रकृति के साथ गहरे संबंध रखते हैं और उनके जीवन में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रकृति से उनका एक अटूट रिश्ता और समन्वय रहता है। वह प्रकृति का मालिक नहीं पर सहभागी होता है। इसके साथ उसका सम्बन्ध सह-अस्तित्व और सहजीविता का होता

है। उनकी गोत्र, प्रथाएँ और मान्यताएँ पर्यावरण की रक्षा और संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई होती हैं।

6. रूढ़िवादी व्यवस्था – आदिवासी समाज रूढ़िवादी व्यवस्था का समर्थन करती है जो कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बजाय संरक्षणवाद का समर्थन करती है।

इसी आदिवासियत से ही आदिवासी समाज एक दूसरे के करीब जुड़ा रहता है और हजारों वरसों से इस पृथ्वी पर अपना वजूद बचा कर अस्तित्व में है तथा जल, जंगल और जमीन को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। इसे अक्षुण्ण रखने के लिये ही हमारे वीर पूर्वजों ने जैसे बिरसा भगवान, वीर बुधु भगत, सिद्धु कान्हों, फूलो ज्ञानो, जतरा टाना भगत इत्यादि के अगुवाई में हजारों आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकुमत से लोहा लिया और अपने प्राण की आहुति दे दी।

आज के सन्दर्भ में आदिवासियत कुँडुख आदिवासियों में –

ऐसे तो कुँडुख या तो ऊँच समाज में आज भी समानता है एवं अन्य समाज की तरह ऊँच-नीच या तो अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होता है। आदिकाल में कुँडुख समाज का, अन्य समाज से दूर पहाड़ पर्वत व नदी नालों के बीच छोटे-छोटे गाँवों एवं कस्बों में सामुदायिक जीवन प्रणाली होता था और वो मुख्यतः खेती बारी, पशुपालन या शिकार के द्वारा जीवन यापन करता था। अतः, समतावादी व्यवस्था, उनके लिये बाध्यता रही होगी, और ये उनके सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया होगा। समाज एवं गाँव में सभी का जन्म, कर्म, लालन-पालन, भरण-पोषण, नाचना-गाना इत्यादि एक ही परिवेश में होता होगा, अतः उनमें जिन्दगी के जीवन दर्शन को समझने में एक रूपता थी चूँकि उनके जीवन शैली में बाहरी लोगों का प्रभाव बहुत कम या नहीं के बराबर होता होगा। अतः वह बाहरी संस्कृतियों से दूर रहने के कारण अपनी आदिवासियत को अक्षुण्ण रख पाया और अपने अस्तित्व को भी सजों के रख पाया।

परन्तु, आज के इस बदले हुए परिवेश में, खास करके अंग्रेजों के आगमन के पश्चात शासन व्यवस्था

परिवर्तन, राजतंत्र से गणतंत्र, उनके सामाजिक जीवन में बाहरी लोगों के संपर्क में आने से, उनके भाषा-संस्कृति और पहिरावे पर बाहरी लोगों के द्वारा निरंतर अतिक्रमण एवं तिरस्कार होने से उन्हें हीन भावना से ग्रसित होना पड़ा जिससे उनमें बाहरी भाषा-संस्कृति का धीरे धीरे आत्मसात् शुरू हुआ। फिर आधुनिक स्कूली शिक्षा के प्रारम्भ होने के तत्पश्चात् तथा ग्लोबलाइजेशन के कारण चारों ओर से आदिवासियों के भाषा, संस्कृति, धर्म, रोजगार, राजनीति इत्यादि पर अतिक्रमण होने के कारण, उनके जीवन मूल्य और जीवन दर्शन में बहुत ही ज्यादा भिन्नता देखने को मिल रहा है। अतः कुँडुख समाज भी इस आधुनिकता और ग्लोबलीकरण के अतिक्रमण से अछुता नहीं है, और अन्य आदिवासी समाज की तरह ही उनकी आदिवासियत भी क्षीण हो रही है।

उनकी छिन्न भिन्न होती आदिवासियत, निम्न मुख्य कारणों से हो रहा है -

1. संक्रमण और समुदायिक असंतुलन - ग्लोबलीकरण के कारण आदिवासी समुदायों में बाहरी संस्कृतियों और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास के प्रभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे समुदायिक संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है और आदिवासी भावनाओं और संस्कृति को खतरे में डाल रहा है।

2. भौतिक परिवर्तन और अभिव्यक्ति के स्थानों की हानि - वन्य जीवन की हानि, जलवायु परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, स्थानीय आदिवासी समुदायों को उनके ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की क्षति वा लुप्त हो रही है, जिससे उनकी आदिवासियत सहेजने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

3. शिक्षा और सम्प्रदायिक ज्ञान की कमी - आधुनिकीकरण के समय में, बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा दीक्षा से वंचित रखने से आदिवासी समुदायों की पारम्परिक ज्ञान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। इससे आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करने की क्षमता कमजोर हो रही है।

4. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबंध - कई बार सरकारी नीतियाँ और सामाजिक प्रतिबंध आदिवासी समुदायों के संस्कृति और जीवनशैली को प्रभावित कर रही हैं। इससे उनके आदिवासी भावनाओं की समृद्धता और सहेजने की क्षमता पर असर पड़ रहा है।

5. संसाधनों की अव्यवस्था - आदिवासी समुदायों के लिए स्वाभाविक संसाधनों की अव्यवस्था और उनके पहुँच की कठिनाई से संरक्षण नहीं हो पा रहा है।

6. आधुनिक शिक्षा व्यवस्था - हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था धुमकुड़िया में, शिक्षा का माध्यम लिखित रूप में न होकर के मौखिक रूप में होता था, चूँकि उस समय हमारे समाज की अपनी कोई लिपि नहीं होती थी। अतः हमारे पास हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गयी हमारी भाषा-संस्कृति, जीवन दर्शन और जीवन मूल्य इत्यादि का कोई संग्रह, किताब या ग्रंथ नहीं है, जिस पर हम गर्व कर सकें और उसका अनुकरण कर उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। वहीं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हमारी प्रारम्भिक शिक्षा, हमारी भाषा में न होकर, बाहरी भाषा में और बाहरी संस्कृति की ही हो रही है जिससे हमें हमारी भाषा-संस्कृति पर हीन भावना की उत्पत्ति हो रही है और हम बाहरी भाषा-संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

7. धर्म परिवर्तन - आदिवासियों के धर्म परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक दबाव, शिक्षा एवं विकास, सांस्कृतिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण इत्यादि के प्रभाव से हो रहा है जिससे उनकी जीवन शैली, जीवन दर्शन और जीवन मूल्यों को उसी धर्म के अनुसार ही आत्मसात् कर रहे हैं अतः हमारी संस्कृति में बदलाव देखने को मिल रहा है। इन प्रमुख कारणों के अलावा, विभिन्न स्थानीय, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत भी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है। आजादी के पहले तक, ब्रिटिश शासन काल में, जनगणना के कॉलम में भी आदिवासियों का एक विशिष्ट और पृथक धर्म कॉलम होता था, जिससे वो अपनी अलग पहचान दर्ज करा सकता था और गौरवान्वित महसूस करता था। परंतु आजादी के उपरांत, तब की शासन व्यवस्था, इसे अलग कॉलम देना गैरजरूरी समझा।

8. पेशा परिवर्तन - बढ़ती आबादी, सरकार की नीति और परम्परागत खेती बारी और पशुपालन इत्यादि में कष्टदायक जीवन व अलाभकारी होने के कारण लोग शिक्षित होने के तदुपरांत अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए नौकरी पेशा या अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं जिससे उनके परम्परागत सामुदायिक जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है। आजकल तो आदिवासी युवक युवतियाँ, गाँव से

खेती बाड़ी का काम को त्यागकर षहर में कुल्ली कबाड़ी, रेजा और आया काम करने में भी गर्व महसूस कर रहे हैं। और इस कारण एसई भी उनकी आदिवासियत क्षीण हों रही है।

9. सोशल मीडिया — आजकल, मोबाईल फोन जिन्दगी का एक अभिन्न अंग हो गया है, पर इसकी जरूरतों के साथ ही इसमें आसानी से उपलब्ध अन्य समुदायों की संस्कृति बच्चों को उनकी ओर प्रलोभन और अकर्षित करते हैं और उसे वे आत्मसात् कर रहे हैं।

10. अंतरजातीय विवाहरू आज कल उच्च शिक्षा और नौकरी पेशा इत्यादि के लिये गाँव से निकल कर षहर में जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ वे अन्य जातियों के संपर्क में आते हैं और षादी के सूत्र में बंध जाते हैं जिससे वो अपनी भाशा और संस्कृति को बरकरार नहीं रख पाते हैं।

11. डेमोग्राफिक बदलाव — प्रशासन ने हमें और राज्यों की तरह, आदिवासी समाज को एक अलग राज्य नहीं दिया जिससे, बाहरी लोग भी रोजगार और जीविका के लिए आदिवासी क्षेत्र में आकर बसने लगे तथा वे लोग भी अपने साथ अपनी भाशा और संस्कृति को साथ में लेकर आये और हमारी आदिवासी भाशा संस्कृति उनका सामना नहीं कर पायी और बौनी साबित हुई। खास करके जहाँ जहाँ औद्योगिकरण ज्यादा हुआ वहाँ सबसे ज्यादा बाहरी लोग आकर बस गये और इन जगहों पर सबसे अधिक आदिवासियत खत्म हुई। अतः हम बाहरी भाशा संस्कृति के प्रभाव में आकर उसे अपनाने लगे और इससे भी हमारी भाषा संस्कृति क्षीण हो रही है।

12. हीन भावना से ग्रस्त — बाहरी लोगों ने हमें हमेशा से जंगली, अविकसित, असभ्य और हमारी खान-पान, पहिरावा, बोली और बर्ताव इत्यादि का मजाक बनाया, हमें तिरस्कृत किया और नीचा दिखाया जिससे हम हीन भावना से ग्रसित होते चले गये और हमने अपनी भाशा संस्कृति की उपेक्षाकर बाहरी भाशा संस्कृति को ज्यादा तरजीह देना उचित समझा। अतः अपनी अज्ञानता के कारण अपनी ही भाषा संस्कृति को हमने परित्याग करना शुरू कर दिया।

13. कुँडुख समाज में अवधारणा — गाँव में ऊँरँव समाज की जीवन पद्धति में समानता रहता है चूँकि उनका आर्थिक स्थिति और पेशा एक बराबर होता है।

परंतु वही गाँव से लोग जब दूर षहर में नौकरी पेशा या रोजगार में चले जाते हैं तथा षहर में ही अन्य समाज के लोगों के साथ जीवन यापन करते हैं तो उनके रोजमर्रा की जीवन पद्धति में काफी बदलाव होता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अच्छी हो जाती है और अपना जीवन स्तर अपने षहरी पड़ोसियों के बराबर ही बनाये रखने की भी बाध्यता महसूस होती है। अतः इस नये परिवेष में, वो गाँव वालों से अपने षहरी जीवन स्तर के अनुसार ही एक आदर सम्मान की आषा रखते हैं। साथ में उनके गाँव घर के लोग भी उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को देखकर कुछ आर्थिक मदद की अपेक्षा करते हैं ताकि उनका जीवन स्तर भी उन्हीं के बराबर रहे। इससे उनका गाँव घर जाने का सिलसिला कम होने लगता है और इस तरह से उनके बच्चे अपनी भाशा संस्कृति से वंचित हो जाते हैं।

14. पारंपरिक कानून व्यवस्था — सरकारी कोर्ट कछाड़ी के आ जाने से भी धीरे धीरे लोग अपने पारंपरिक पंच और पड़हा व्यवस्था को छोडकर फैसले के लिये कोर्ट की ओर रुख करने लगे हैं।

उपरोक्त कोई भी कारणों से या कई सारे कारणों के परिणाम स्वरूप और या कुछ अन्य कारणों से भी आजकल आदिवासी सामुदायों में भाशा, पहिरावा, अचार विचार, जीवन मूल्य, धार्मिक आस्था और जीवन दर्षन या यों कहें उनकी संस्कृति में भिन्नता देखने को मिल रहा है। अतः, यद्यपि हम सब हैं तो एक ही समाज से, पर उपरोक्त कारणों से यहाँ तक कि आदिवासी षब्द में भी षायद स्पष्टतापूर्वक एकरूपता की कमी है, या ये बोलें हमारी आदिवासियत ही धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है।

छिन्न भिन्न होती आदिवासियत के दुष्परिणामरु आदिवासियत का छिन्न-भिन्न होना आदिवासी समुदायों के लिए कई गंभीर दुष्परिणाम ला रहा है। ये परिणाम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हानिकारक हो रहे हैं जिससे वो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

कुछ प्रमुख दुष्परिणाम के उल्लेख निम्नलिखित हैं —

1. सांस्कृतिक क्षति —

• पारंपरिक ज्ञान और भाषा का ह्रास आदिवासी समुदायों की भाशाएँ और पारंपरिक ज्ञान खत्म हो रहे हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही है।

• रिवाज और परंपराओं का विनाश – त्योहार, नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं, जिससे सांस्कृतिक पहचान खो रही है।

2. सामाजिक अस्थिरता –

• सामाजिक संरचना का विघटन – समुदायों के बीच पारंपरिक सामाजिक बंधनों और प्रणालियों का कमजोर होना भी शामिल है, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है।

• सामाजिक बहिष्कार – मुख्यधारा की संस्कृति में घुलने-मिलने के प्रयास में, कई बार आदिवासी लोग अपनी जड़ों से कट रहे हैं और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं।

3. आर्थिक समस्याएं –

• आजीविका का नुकसान – पारम्परिक खेती, शिकार और वनोपज पर आधारित आजीविका के साधनों का नुकसान, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं।

• भूमि और संसाधनों का अधिग्रहण – औद्योगिकीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण, जिससे उनका जीवनयापन मुश्किल होता जा रहा है।

4. पर्यावरणीय प्रभाव –

• वन्य जीवन और पारिस्थितिकी का विनाश – आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई और खनन जैसी गतिविधियाँ, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है।

• जलवायु परिवर्तन – पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान का ह्रास, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता कम हो रही है।

5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य –

• मानसिक तनाव – सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के क्षरण के कारण आदिवासी समुदायों में मानसिक तनाव और अवसाद की समस्याएँ बढ़ रही हैं।

• स्वास्थ्य सेवाओं की कमी – पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों का ह्रास और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं।

6. राजनीतिक और अधिकारों का हनन –

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी – आदिवासी समुदायों की आवाज और प्रतिनिधित्व कम हो जाता है,

जिससे उनकी समस्याएँ और अधिक उपेक्षित हो रही हैं।

• मानवाधिकारों का उल्लंघन – भूमि और संसाधनों के अधिग्रहण में मानवाधिकारों का उल्लंघन, जिसमें हिंसा और विस्थापन हो रहे हैं। अतः आदिवासी समाज का बेदखल हो रहा है जिससे कि शहरी क्षेत्रों में डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है।

इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं की सुरक्षा और संवर्धन, आर्थिक सहायता और विकास, और उनके अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से इन समुदायों के सशक्तिकरण में सहायता मिल सकती है।

आदिवासियत सहेजने की जरूरत एवं उपाय – आदिवासियत को सहेजने की आवश्यकता कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि – (क) यह वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, (ख) यह सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और (ग) पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएँ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में सहायक हो सकती हैं। यहाँ कुछ उपाय और कदम दिया जा रहा है जिनसे आदिवासियत को संरक्षित किया जा सकता है

1. सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा –

भाषा संरक्षण –

• आदिवासी भाषाओं की शिक्षा और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना। स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना।

• भाषाई दस्तावेजीकरण और अनुवाद परियोजनाओं को समर्थन देना।

परंपराओं और त्योहारों का संरक्षण –

• स्थानीय त्योहारों, नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।

• सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों की स्थापना करना, जहाँ आदिवासी कला और इतिहास को प्रदर्शित किया जा सके।

2. आदिवासियों के धर्म की पहचान एवं संरक्षण –

आजादी के पहले की तरह ही, जनगणना के कॉलम में आदिवासियों का एक विशिष्ट और पृथक कॉलम होना चाहिये, जिससे कि उसकी अपनी अस्मिता हो और वो

अपने धर्म और विश्वास को गर्व से अक्षुण्ण रख सके।

3. आर्थिक सशक्तिकरण –

आजिविका के साधनों का विकास –

• पारम्परिक कृषि, वनोपज और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना।

• आदिवासी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना और व्यापार को समर्थन देना।

शिक्षा और कौशल विकास –

• शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाना।

• स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

4. सामाजिक और पर्यावरणीय संरक्षण –

पर्यावरण संरक्षण –

• वनों और जल संसाधनों की रक्षा करना, जो आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

• पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाना और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

सामाजिक संरचना की मजबूती –

• आदिवासी नेतृत्व और पंचायत प्रणाली को समर्थन देना।

• महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दे।

5. कानूनी और राजनीतिक संरक्षण–

कानूनी अधिकारों की रक्षा –

• आदिवासी भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनों का प्रवर्तन।

• आदिवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व –

• आदिवासी समुदायों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करना और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।

• स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में आदिवासियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

6. शिक्षा और जागरूकता –

शिक्षा के माध्यम से जागरूकता –

• आदिवासी इतिहास, संस्कृति और उनके योगदान

के बारे में प्रारम्भिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में होना चाहिये।

• गाँव में पारंपरिक धुमकुड़िया शिक्षा व्यवस्था की भी शुरुवात होनी चाहिये।

• मुख्यधारा के समाज में आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता और समझ को बढ़ानी चाहिये।

इन उपायों के माध्यम से आदिवासियत को सामुदायिक भागीदारी, सरकारी समर्थन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सहेजा जा सकता है, जिससे न केवल आदिवासी समुदायों का विकास होगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी। पर अबतक उरांव समाज खुद सजग होकर इसे सहेजने की कोशिश नहीं करता है तबतक ये क्षिन्न भिन्न होती रहेगी।

आज के इस सामाजिक परिवेश में, ब्रिटिश हुकूमत के आगमन के पहले, राजतंत्र के समय में जो वेशभूषा, पहिरावा और संस्कृति थी, उसको संरक्षित रखने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और शायद इसे हु-ब-हू संरक्षण रखना संभव न हो, परंतु उनकी आदिवासियत को उनके जीवन दर्शन और जीवन मूल्यों को अवश्य ही संजो के रखा जा सकता है जिसे मशहूर आदिवासी कवित्री जसींता केरकेट्टा के आदिवासियत की व्याख्या 'मेरा आदिवासी होना' की परिकल्पना से कर सकते हैं –

मेरा आदिवासी होना।। न साड़ी, न खोपा, न गोदना, न गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम ? अकसर लोग पूछते हैं मुझसे, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ धरती के करीब रहना ही आदिवासी होना है, प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है, नदी की तरह बहना और सहज रहना ही आदिवासी होना है। भीतर और बाहर हर बन्धन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है। और अपने सुन्दर होने के सारे चिन्हों के साथ ज्यादा मनुष्य होना ही आदिवासी होना है। पर किसी के मन में सिर्फ रह गया है कोई गहना और गोदना और कोई नहीं समझ पाता हो क्या होता है आदिवासी होना। तो मैं चाहती हूँ बदले समय में नये सिर से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना। इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर आदिवासी होना।

सम्पर्क हेतु – आयनावरम, चेन्नई

मोबाइल न. 94450 05094

Email: baUlab65@gmail-com

5. परम्परागत आदिवासी समाज और डिजिटल विषयक राजनीति

श्री गजेन्द्र उरांव उर्फ नाना जी उम्र 72 वर्ष थाना सिसई जिला गुमला के रहनेवाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्कूली शिक्षा में बे 9वीं पास हैं। उनका कहना है कि बचपन में उनके माता पिता स्कूल भेजने के स्थान पर बैल-बकरी चराने के लिए भेजते थे। इसपर कार्य में उनका दिल नहीं भरा और वे बड़े भाई के साथ बोकारो के कोयला खादान में काम करने चले गए। पर वहां रहकर खादान में काम करने में भी मन नहीं लगा। फिर वे वापस गांव चले आए। गांव आकर अपने से 6-7 वर्ष छोटे उम्र के साथियों के साथ गांव के स्कूल आर. सी.मिशन यू.पी. स्कूल सैन्दा (सिसई, गुमला) में नामांकन कराये। वहां 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद वे राजकीय मध्य विद्यालय, सिसई में दाखिला लिये और वहां से आगे बढ़कर संत तुलसी दास उच्च विद्यालय, सिसई में दाखिला लेकर 9वीं तक की पढ़ाई पूरी की। कई पारिवारिक कारणों से वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाये, परन्तु गांव में रहकर वे ग्रामीण शिक्षा जैसे विषयों में पारंगत बने।

श्री गजेन्द्र उरांव जी का सामाजिक विषयों पर बारिकी एवं पारखी नजर है। परम्परागत आदिवासियों के बीच का सामाजिक आन्दोलन हो या धार्मिक आन्दोलन, वे मुखर होकर बोलते हैं। श्री गजेन्द्र जी बतलाते हैं कि – परम्परागत आदिवासी समाज के लोग किस तरह तत्कालीन बिहार का आकाल 1966-67 के दौर में भूख मिटाने के लिए ईसाई मिशनरी संगठनों की पैरोकारी की और झूण्ड के झूण्ड गिरजाघरों में शरणागत हुए। राज्य सरकार की सरकारी मशीनरी की मदद के लिए आगे आये गिरजाघरों ने अवसर का भरपूर लाभ लिया, जो समय की धारा में निरंतर बहता गया। इसी उतार-चढ़ाव में बाबा कार्तिक उरांव, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने जा चुके थे। कार्तिक बाबा पहली बार चुनाव हारने के बाद वे परम्परागत आदिवासी समाज की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था, पड़हा का नवजागरण हेतु 1962 में आह्वान कर चुके थे। क्षेत्रीय स्तर पर इस पड़हा नवजागरण का नेतृत्व श्री भिखराम भगत जी कर रहे थे।

इन दिनों आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बाबा कार्तिक उरांव का नाम परम्परागत आदिवासी समाज तथा ईसाई आदिवासी समाज के बीच वाद-विवाद में अकसर हाँ आ ही जाता है। परम्परागत उरांव समाज के लोग बाबा कार्तिक उरांव को अपना मार्ग दर्शक मानते हैं, पर ईसाई उरांव लोग उनके नाम पर आग बबुला हो जाते हैं। इस विवाद का जड़, मुख्य रूप से दो कारण माना गया है – 1. ईसाई आदिवासी लोगों द्वारा आरक्षण का दोहरा लाभ लिया जाना तथा 2. परम्परागत संस्कृति रीति-रिवाज के स्थान पर यूरोपीय सभ्यता-संस्कृति को अपनाकर, अपने से कमजोर आदिवासियों पर जबरन मन परिवर्तन कराना, कहा गया है।

वैसे जनजातीय आरक्षण का लाभ तो आजादी के बाद दोनों ही समूह के लोग ले रहे हैं। परन्तु अल्पसंख्यक कल्याण आरक्षण का लाभ, सिर्फ ईसाई आदिवासी समाज के लोगों को ही मिलता है। इस संदर्भ में कार्तिक बाबा ने अपनी पुस्तिका “बीस वर्ष की काली रात” में कहा है कि – कल्याण के कार्य में यदि – 5.53 प्रतिशत ईसाई को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 192 रु० खर्च होते हैं, तो 95.47 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को प्रति व्यक्ति 74 पैसे खर्च होते हैं अथवा यों कहिए कि अनुसूचित जन जाति के कल्याण पर अगर 01 रूपया खर्च होता है तो एक ईसाई आदिवासी के कल्याण पर 255 रूपये खर्च हो रहे हैं।

इसी तरह भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने तथा संचालन करने का विशेष कानूनी प्रावधान मिला है। जबकि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को यह लाभ अथवा व्यवस्था नहीं है। इस कानून का लाभ ईसाई आदिवासियों द्वारा अपने समूह के लोगों के लिए किया गया और वे राष्ट्र

की मुख्य धरा में जुड़ते गये। ईसाई लोगों को अल्पसंख्यक स्कूल-कालेज तथा संस्थान खेलने तथा अपने तरीके से संचालन करने की छूट है, जिसपर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का सीधा प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं है। पता नहीं, देश की जनता एवं सरकार, जनजातीय कल्याण के इस पहलु पर ध्यान भी है या नहीं ?

इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चिंतन-मंथन कर तथा समाज की दुर्दशा के कारणों को ढूँढते हुए बाबा कार्तिक उरांव द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन विधेयक 1967, दिनांक 10 जुलाई 1967 को लोकसभा में प्रविष्ट कराया गया। इसपर विचार-विमर्श के बाद लोकसभा की संयुक्त समिति को सौंपा गया। इस संदर्भ में 17 नवम्बर 1969 को लोकसभा की संयुक्त समिति का सिफारिश शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसूची 2 कंडिका (2अ) में यह भी था कि – “2अ० कंडिका 2 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने जनजाति आदि मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई, इस्लाम आदि धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।”

लोकसभा की संयुक्त समिति ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था। इसपर लोक सभा में 01 वर्ष तक बहस नहीं हुई। इस सिफारिश पर भारत के कोने-कोने से देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर ईसाई मिशनरियों का दबाव आने लगा। इस क्रम में 50 सांसदों के हस्ताक्षर से ईसाई सांसदों ने सरकार पर दबाव बनाया कि वे संयुक्त समिति की सिफारिश को विरोध करें।

दूसरी ओर बाबा कार्तिक उरांव द्वारा 348 संसद सदस्य (322 लोकसभा तथा 26 राज्यसभा सदस्य) के हस्ताक्षर के साथ, दिनांक 10 नवम्बर 1970 को संयुक्त समिति की सिफारिश को लागू करने हेतु सरकार के सामने रखा गया। इस विधेयक पर दिनांक 16 नवम्बर 1970 से लोकसभा में बहस आरंभ हुआ। इसी बीच दिनांक 17 नवम्बर 1970 को सरकार की ओर से विधेयक में संशोधन करते हुए संयुक्त समिति की सिफारिश को विधेयक से हटा दिया गया। सरकार में दो ईसाई उपमंत्री थे, जिन्होंने संशोधन विधेयक का स्वागत किया तथा संयुक्त समिति की सिफारिश का विरोध किया। इस विधेयक पर कार्तिक बाबा दिनांक 24 नवम्बर 1970 को 55 मिनट तक बहस किये। विधेयक पर बहस करते हुए अंत में उन्होंने कहा – “या तो संयुक्त समिति की सिफारिश को हटाया जाए या कार्तिक उरांव को इस दुनिया से हटा दिया जाए।” लोकसभा में सदन की गंभीरता को देखते हुए विधेयक पर उसी सत्र में विधेयक पर बहस कराने के आश्वासन पर स्थगित किया गया। परन्तु दिनांक 27 दिसम्बर 1970 को लोकसभा भंग हो गई और आदिवासी समाज के जीवन में ज्योति नहीं आयी।

उपरोक्त संदर्भ में डिलिस्टिंग जैसा विषय, वैसे लोगों के साथ चर्चा में आती है जो आदिवासी से ईसाई बने हों। पर यदि धर्म ही आधार है तो आदिवासी से मुस्लिम बने लोगों पर चर्चा क्यों नहीं होती है ? यह तथ्य है कि भारत देश के कई हिस्सों में आदिवासी से मुस्लिम बने लोग आज भी अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में देश की बड़े राजनैतिक दल, क्या, आदिवासियों के साथ न्याय कर पाएंगे या बड़ा राजनैतिक दल आदिवासियों को वोट बैंक का स्रोत मात्र मानते रहेंगे ??

संदर्भ :- बीस वर्ष की काली रात –
लेखक स्व० कार्तिक उरांव।

शोध एवं संकलन :- सुश्री नीतु साक्षी टोप्पो,
डिबीडीह, रांची एवं श्री गजेन्द्र उरांव,
सिसई, गुमला।



6. एनईपी 2020 एवं आदिवासी समाज में धुमकुड़िया की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), देश में लग चुका है। यह शिक्षा नीति, झारखण्ड में वर्ष 2022 से लागू है। इसके तहत आदिवासी बहुल क्षेत्र में 5 आदिवासी भाषा (कुँडुख/उराँव, मुण्डा, खड़िया, हो एवं संताली) को मातृभाषा के रूप में 1ली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई-लिखाई कराये जाने की योजना आरंभ की जा चुकी है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में झारखण्ड वासियों के लिए त्रिभाषा शिक्षा (हिन्दी, अंगरेजी और मातृभाषा) नीति को आधार बनाया गया है।

यह पाठ्यक्रम योजना 5+3+3+4 के रूप में प्रारूपित है। इसमें से प्रथम 5 को 3+2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इन 5 में से पहला 3 वर्ष का समय, पूर्वशिक्षा या शिक्षा वाटिका शिक्षा को सूचित करता है तथा बाद वाला 2 वर्ष, क्रमशः 1ली एवं 2री कक्षा का समय सूचक है। अर्थात् अब अभिभावक अपने बच्चों को 3 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद सरकार द्वारा नियोजित पूर्वशिक्षा केन्द्र में भेजेंगे, जहाँ वे नर्सरी में 1वर्ष, एल.के.जी में 1 वर्ष तथा यू.के.जी में 1 वर्ष की तरह शिक्षा केन्द्र भेजा करेंगे। इस तरह उक्त 5 वर्ष तक सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्र में बच्चा 2री कक्षा उत्तीर्ण करेगा। उसके बाद 5+3+3+4 में से पहले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चे, क्रमशः 3रा, 4था एवं 5वाँ कक्षा तय करेगा तथा उक्त 5+3+3+4 में से अगले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 6ठा, 7वाँ, 8वाँ कक्षा तय करेगा। इसी तरह उक्त 5+3+3+4 में से अंतिम 4 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ एवं 12वाँ कक्षा तय करेगा। इस नई योजना में 10वाँ बोर्ड को निरस्त किया गया है। अब 10वीं के स्थान पर 12वीं बोर्ड होगा।

वर्तमान समय के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में पूर्व शिक्षा योजना हेतु 3 साल के बच्चे के लिए विशिष्ट स्कूली व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इस नई व्यवस्था

के अंतर्गत 4 वर्ष से 6वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस तरह यदि पूर्व शिक्षा या शिक्षा वाटिका शिक्षा योजना को आंगनवाड़ी से जोड़ा जाता है तो यह प्रश्न उठेगा कि – क्या, सभी (कुँडुख/उराँव बहुल क्षेत्र) क्षेत्र के आधे से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाएँ उक्त भाषा एवं उस भाषा की लिपि में लिखाई पढ़ाई नहीं जानते हैं। क्या, समाज के लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे! अब समाज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा योजना पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श एवं निर्णय करने की आवश्यकता है।

वैसे पूर्व में सभी गाँव-टोला में अवस्थित पारम्परिक सामाजिक पाठशाला धुमकुड़िया में उराँव समाज के बच्चों को 7वें वर्ष में प्रवेश कराया जाता था। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों के लिए बैठने के लिए कण्डो या पिटरी, रोषनी के लिए टट्टी और करंज तेल के साथ माघ महीने में धुमकुड़िया पहुँचाया करते थे। आरंभिक समय में लड़के-लड़कियाँ सभी साथ-साथ उठते-बैठते तथा जीवन जीने के तरीके सीखा करते थे। उम्र बढ़ने के साथ लड़कियों का मानसिक तथा शारीरिक विकास होने के साथ जब उनका मासिक धर्म आरंभ होता था तो उन्हें पेल्लो एड़पा प्रवेश कराया जाता था। पेल्लो एड़पा में लड़को का प्रवेश वर्जित होता था। धीरे-धीरे उम्र बढ़ने के साथ शादी के लिए बातचीत तय होने पर लड़के-लड़कियों को धुमकुड़िया से विदाई दी जाती थी। उराँव आदिवासी लोगों में धुमकुड़िया, एक सामाजिक पाठशाला सह कौशल विकास केन्द्र रहा है। धुमकुड़िया में 4 से 6 वर्ष के बच्चे खेल-खेल में धुमकुड़िया के कार्यों में शामिल होते हैं, पर सामाजिक विधान के अनुसार उन्हें 7वें वर्ष में धुमकुड़िया प्रवेश कराया जाता है।

इस पारम्परिक धुमकुड़िया में सुनकर बोलने तथा देखकर बोलने की कला विकसित थी, परन्तु देखकर लिखने एवं पढ़ने की कला विकसित नहीं थी, जिसके चलते पारम्परिक धुमकुड़िया, आधुनिक स्कूल का सामना नहीं कर पाया और समय की तुलना में पिछड़कर, बिछड़ गया।

इस विषय पर कई सामाजिक चिंतक एवं शिक्षाविद, धुमकुड़िया के पुनर्जागरण की बातें करते हैं। अब तो कई अधिकारी भी धुमकुड़िया पुनर्जागरण को अच्छा मान रहे हैं। इस संदर्भ में झारखण्ड के प्राशासनिक अधिकारी पर दिनांक 13 मार्च 2022 को सम्पन्न “कुँडुख भाषा, शिक्षा एवं धुमकुड़िया” विषयक कार्यशाला में मुख्य अतिथि, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल ने कहा – “आदिवासियों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के उपाय पर भी कार्य करना होगा। सरकार द्वारा “धुमकुड़िया” निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, पर धुमकुड़िया की आत्मा को जगाने का कार्य तो समाज के लोग ही करेंगे।”

वर्तमान परिस्थिति में धुमकुड़िया का संवर्द्धन समय की मांग है। स्कूली शिक्षा के साथ सामाजिक शिक्षा भी दिया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उम्र के बच्चों को शिक्षा तथा देखरेख आवश्यक है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चों को देखरेख तथा समाज में जीवन-यापन के तरीके पर गौर करने की कमी दिखती है।

परम्परागत आदिवासी समाज को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है –

1. वर्तमान नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें पूर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी को स्थान दिया गया है, परन्तु वर्तमान समय

में अधिकतर आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं मातृभाषा शिक्षा में निपुण नहीं होने के चलते मातृभाषा शिक्षा योजना की बेहतरी की उम्मीद कम है। पर सरकारी व्यवस्था में यदि परम्परागत धुमकुड़िया शिक्षा व्यवस्था को स्थान मिलने से आदिवासी समाज के बच्चे अपनी सामाजिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा में भी बेहतर कर सकते हैं।

2. NEP 2020 के अन्तर्गत पूर्वशाला या आंगनवाड़ी की तरह धुमकुड़िया के लिए Para teacher के अनुशिक्षक एवं सरकारी पठन-पाठन सामग्री सरकारी व्यवस्था से सहायता मिलनी चाहिए ? वर्तमान समय में सरकारी पठन-पाठन सामग्री का आधार हिन्दी एवं देवनागरी लिपि है। जबकि कुँडुख भाषा की अपनी लिपि, तोलोंग सिकि भी है एवं झारखण्ड तथा प0 बंगाल सरकार में मान्यता प्रदत्त है। ऐसे में मातृभाषा शिक्षा, तोलोंग सिकि, लिपि में लिप्यंतरण करके किया जा सकता है।

3. आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बाद आदिवासी परम्परागत शिक्षा व्यवस्था चकनाचूर हो गया और आदिवासी समाज आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के चाटुकारिता में फंसता गया। आज के समय में शहरी क्षेत्र में अभिभावक अपने बच्चों को संभाल ले रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावक इस चुनौति का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान समय के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाना समझा जाता है जो शायद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए पूर्ण आजादी का कारण बनता जा रहा और 9वीं-10वीं कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते वे संभल नहीं पा रहे और डर एवं सामाजिक दबाव में ईट भट्टा में काम करने जाने लगे हैं। शायद आदिवासी समाज सरकारी योजना का लाभ बेहतर ढंग से नहीं ले पा रहा हो। इस स्थिति में धुमकुड़िया शिक्षा बेहतर विकल्प हो सकता है।

4. गांव स्तर में बच्चों की कमतर शिक्षा के कारण लोग नशाखोरी के चक्कर में फंसते जा रहे रहे हैं। यदि

वाल्यकाल में धुमकुड़िया के माध्यम से शिक्षा का बेहतर अवसर मिले तो नई पीढ़ी को नशापान एवं Drug addiction से बचाया जा सकता है।

5. वर्तमान समय में आदिवासी समाज में एक अलग तरह की परिस्थिति बन गई है। गांव घर के युवा या मर्द किसी के खेत में मजदूरी करने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार 2 रुपये किलो चावल दे रही है तो दूसरे के खेत में मजदूरी क्यों करें। अब मर्दों की ऐसी मानसिकता ने उनका अपना खेत भी बंजर बनता जा रहा है। इसी तरह गांव के कम पढ़े लिखे मर्द, नशाखोरी और आलसीपन ने परिवार के प्रति गैरजिम्मेदार होते जा रहे हैं और परिवार में आकस्मिकी के समय जमीन बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति से बाहर आने के लिए समाज में धुमकुड़िया शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना होगा, जो बचपन से ही बच्चों को अपने एवं परिवार के प्रति जबाबदेह और जागरूक कर सके और समय पर सामाजिक स्तर पर मदईत-पसरी के माध्यम से समाज एवं परिवार के हित में कार्य कर सके।

6. इन दिनों गांव स्तर में बच्चों की शिक्षा का स्तर गिरने के चलते, वे शहर के बच्चों से पिछड़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार एवं समाज को मिलकर धुमकुड़िया में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे बचपन से ही गांव के बच्चों का भी नई तकनीक पर ध्यान जाने से वे शहर के बच्चों के साथ मुकाबला करने के लिए धुमकुड़िया के माध्यम से शिक्षा का बेहतर अवसर का लाभ ले सकेंगे।

इन सबके होते हुए नई शिक्षा नीति 2020 आने वाले समय में आदिवासी बहुल क्षेत्र में मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से समाज में जागृति तथा शिक्षा के प्रति उत्साह जगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति के लिए ग्रामीण स्तर में मातृभाषा शिक्षा, अपने परम्परागत तरीके के साथ अर्थात्

धुमकुड़िया शिक्षा के साथ आधुनिक तरीके का समायोजन करते हुए देश की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के विकास का द्वार खोला जा सकता है।



शोध-संकलन -

डॉ० नारायण उरांव "सैन्दा"

ग्राम - सैन्दा, थाना - सिसई,

जिला - गुमला, झारखण्ड।

मो0न0 - 9771163804

7. बसा-नना गे सेन्दरा दिम बिसुसेन्दरा बाताःरा (सोनो-रूपो गिधि गही लवरना) (उराँव समुदाय एवं सेमल पेड़ और दो गिद्ध की पौराणिक लोक-कथा)

बअनर हुल्लो परिया नु कुँडुख खोंडहा आँगओल अकय ससईत नु रहचा। एँड गोटंग सोनो गिधि-रूपो गिधि (White Vulture) आल जियन केरमे-केरमे पिटा-मुंज्जा लगिया। आद आःलर गही उगता-पगसिन ओन्टे कोहाँ ले सराहरा सिम्बाली मन्न नु खोता कमआ लगिया अरा आःल खद्दारिन नेप्पा-नेप्पा तंगआ खोता मइय्याँ तंगआ खद्द गे चरा कमआ लगिया।



आ सोनो-रूपो गिदही 12 चान नू आँगओल बरगी राःजी ती बरअम लगिया अरा आल खद्दारिन नेप्पा की होआ लगिया अरा तंगआ खोता नू तंगआ खद्द गे चरा कमआ गे पिटा लगिया। बअनर अदि गही बरचका खोखा एका-एका से उल्ला कट्टा लगिया अन्नेम नितकिम ओरोत आल जिया खोंडहा ती नठारआ लगियर। गोटे खोंडहा नु हुही चूचकी रहचा का एँड गोटंग सोनो-रूपो गिधि बरई दरा आल खद्दारिन निप्पी-पिसी दरा पिटी-मूखी। खोंडहा ता आःलर जुलुम जुट्ट लग्ग ईरयर पहें अदिन लवआ पोल्लर। सोनो गिधि अंजखंज परता मझी कोहाँ अरा सुरंग ले सिम्बाली मन्न मईय्याँ तंगआ खोता कमआ लगिया,

एकसन अँडसर की अदिन लवअना, खोंडहा ता आःलर गे मसकिल मंज्जकी रहचा। पद्दा ता आःलर अदिन लवआ गे पद्दा गईनका जुमुरअर की सेन्दरा बेःचा लगियर पँहे अदिन लवआ पोल्लर।

अन्तिले खडिदयर, हाःरचर की धरमे सिन गोहरारआ हेल्लर - अना धरमे, नीन एमन उरमिन सिरजन-बिरजन नंज्जकय अरा पोसआ-पर्दआ लगदय। नीन उरमी नु उंगु अरा ओरमर ही उरबय तलदय। नीनिम एमन बछाबअदय नेकआ। एःम गा एमहय पया-पूरती नंज्ज ईःरकम पहें ससईत ती उरखा पोल्ला लगदम। एःम नेःकन हूँ ससईत मल ननदम पँहे एःम ससईत ती बछरआ पोल्ला लगदम। अक्कु धरमे निंगहय दिम भरसा, निंगहय तिम असरा, नीनिम एमन अरा आल जियन बछाबअदय नेकअन।

गोटे आल खोंडहा का, कुँडुख खोंडहा ही एन्ने भभनारना मलता ओहरा बिनती ननना धरमे संवग गूटी अँडिसया केन्धेल अरा राःजी किर्रना ही बेडा बरना रहचा केन्धेल का अन्ती धरमेस ही लिला, का धरमे संवंग गही छया-भया ! उन्दुल ओन्टा ठेपरा जोंःखस पूरबे तरती कुँडुखर गही पद्दा मझी डेरा-बसा बेद्दा गे अँडिसयस। बअनर आ कुक्कोस ही मुहटन एःरर की पद्दा ता जोंःखर अनभनिय्याँ अलखनर अरा आःसिन चिडिगनुम-पडगनुम पद्दा ती तरकूटी नना चिअआ लगियर। एन्नेम ई पद्दा ती आ पद्दा मन्नुम-मन्नुम धुँधरुक मना हेल्लरा। बीःडी पुत्तना बेडा नु आस ओन्टे पद्दा कूटी ता ओन्टे रँढिया पच्चो (विधवा वृद्ध बुढिया) ही एडपा अँडिसयस। असन अँडसर आ पच्चो हेदे माःखा बारी पाही रअआ गे ओहरा नंज्जस। पच्चो बाःचा - बरा जुनु अन्ति बेटा, एंगहय गा खद्द न खर्रा, नीन रअओय होले एंगगा हूँ दःव लग्गो अरा एंगहय जिया हूँ साःलो। अन्तिले आ ठेपरा जोंःखस रँढिया पच्चो गही एडपा नु रअआ

हेल्लरस। पच्चो एका बाःरी नलख गे बहरी काःलो आ बेड़ा नू आ जोंःखस पच्चो ही एड़पा ता नलखन पँडसा चिअआ लगियस। पच्चो लस्सी नना गे बहरी काःलो का ओना—मोखा गे खुरजी समा नना काःलो होले आ जोंःखस एड़पा ता नलखन चेमचेम ले नंज्जका रओस। पच्चो हूँ आस ही नलखन एःरर खुसमाःरआ लगिया अरा तंग नतीस लेखआ घोखअर की आःसिन एमतआ खजरतआ हेल्लरा। पच्चो ही एड़पा नु रअनु—रअनुम आ जोंःखस चेमचेम लेकन रआ हेल्लरस। अन्तिले आस पद्दा ता जोंःखर—पेल्लर गने ओक्का—ईजआ हेल्लरस। आ ठेपरा जोंःखस सेन्दरा बेःचना नु पंखराज रहचस। अवंगे पद्दा ता जोंःखर आःसिन पईत्तआ हेल्लरर अरा सेन्दरा बेचना नु मुन्धहारे नना हेल्लर। आस ओन्द रज्ज नु कौंहा—कौंहा तोम्बन खण्डा चिअआ लगियस। एकअम कौंहाँ बनयाँ किंको आस ही छमहें ती कट्टा पोल्ला लगिया। सेन्दरा बेःचना नु पंखराज रअना चड्डे पद्दा—खेप्पा अरा अहटा—पहटा ता जोंःखर—पेल्लर आस गही कत्थन मेना हेल्लरर। ठेपरा जोंःखस हुं ओरमा खद्वर अरा जोंःख—पेल्लारिन अनआ—मनआ दव कत्था अरा लूरन तेंगा लगियस। ठेपरा मननु हुं पंखराज अरा लूरगर मनना चड्डे आःसिन खोंडहातर लिटिबीर बअआ हेल्लरर। खोंडहा नु बरना अरा खोंडहा गने रअना दोयमून्द बछर (12 चान) पूरआ हेल्लरा। अन्ने बेड़ा नुम उन्दुल खोंडहा ता आःलर आ रँदिया पच्चो ही एड़पा बरचर दरा पच्चोन चिडिगयर अरा बाःचर — निंग नतीस लिटिबीर भईर बाःरओस का नलख हुं ननोस। निंग नती सिन आःनय, आःसिम ई ससईत ती बछरना गही उरजिस तेंगोस अरा ननोस। अन्तिले पच्चो लिटिबीर सिन बाःचा — एरा नतिया अक्कु नीःनिम खोंडहन उबार नना ओंगोय।

पच्चो अरा पद्दा ता आलर गही कत्थन मेनर आ जोंःखस पदियारिन धिरजा (ढाढस) चिच्चस का — आस आ सोनो गिधिन पिटोस दरा नटाबओस चिओस। आ लिटिबीर ठेपरा जोंःखस बाःचस — एंग्गा 12 मन गही ओन्टा एड़थ (धनु) अरा 05 मन गही मून्द (तीन)

गोटंग कन्ना अरा 7 मन गही ओने टोंग'ए कमतआ चिअआ। जोंःखस गही कत्थन मेनर ओरमा पदियर आ जोंःखस गही आईनका बेसेम एड़थ—कन्ना अरा टोंग'ए कमतआ हेल्लरर। इबड़ा संजगी कमरका खोःखा पदियर संघड़ा नना—नना जोंःखस गही तिगका बेसेम सोनो गिधि गही रअना अड्डा तरा होच्चर। सोनो गिधि हूँ पँडय्या गलि मुँजुरना खोखा बिड़ना गलि ओःरे मनना बेड़ा नुम अन्धवारनुम बरआ लगिया अरा आःलारिन नेप्पा—पेसा लगिया। एन्नेम बेड़ा कट्टिया अरा सोनो गिधि ही ससईत बेड़ा अँडसा हेल्लरा। पईयाँ बोंगना अरा बिड़ना ओरे मनना बेड़ा नु आद बरचा अरा आ सरा—हरा कौंहाँ सिम्बाली मन्न नुम खोता अट्टिया अरा बी टिड्डा दरा लेद्दा खद्व ही उड़ान मनना गूटी खोता नुम तंगआ खद्वारिन पोःसआ गे आलारिन नेप्पा—पिटा की चरा कमआ गे अजगो—इजगो कुद्दा हेल्लरा। इबड़ा कत्थन पद्दा ता जोंःखर, आ लिटिबीर ठेपरा जोंःखासिन तिगगयर। इजगो लिटिबीर ठेपरा जोंःखस ही डिड्ढ ती (साहस से) पदियर सेन्दरा बेःचा ओरे नंज्जर। अंजखंज परता मझी सुरंग ले कौंहा सिम्बाली मन्न मईय्या अरगना नरमहा आलर गे बाईह पोल्ला मना लगिया। अदि संगेम सोनो गिधि गही खिलपईत, एका तरती बरओ दरा नेःकन पेसो की होओ अदिन ने हूँ अखआ पोल्ला लगियर। अन्ने बेड़ा नु आ सिम्बाली मन्न गुसन काःला गे ओरमर एलचा लगियर। एन्नेम कुद्दनुम—नुंगनुम का, तवगर ईरनुम एँःड उल्ला (दो दिन) कट्टिया केरा। मून्दता उल्ला (तीसरा दिन) सेयान जोंःखस तंगआतिम आ ओत्था टोंग'एन धरचस दरा टोडंग—परता ता अंजखंज अड्डुन चतरआ ओःरे नंज्जस। अंतिले अड्डा कमअर आ ओत्था एड़थ—कन्नन असन होच्चस। परता मईय्याँ चपईल मझी एन्ने अड्डा कमचस का सोनो गिधि गे एःरा—नेप्पा खतरी मसकिल मंज्जा केरा। भईर उल्ला अजगो—इजगो मन्नुम कट्टिया अरा सोनो गिधि हू दव ले खोता नु ओक्का रहचा। अन्तिले ओःडा—खाःखा ही खोता नु किरना बेड़ा मना लगिया। आ बेड़ा नुम सोनो गिधि तंगहय खोता नु अँडिसया। इजगो लिटिबीर ठेपरा

जोंःखस मून्ता कन्ना तुरु रज्ज ले सोनो गिधि गही खोतन खत्ताचस, अदि खोःखा ँँडता कन्ना ती ओन्द रज्ज नुम आ कोंहा सिम्बाली मन्नन हड़हुड़ ना खत्ताचस चिच्चस। खोता अरा डेरा बसन नठारका एःरर सोनो गिधि अंधवारनुम आलर मईयाँ मंडरारआ हेल्लरा, मुन्दा लिटिबीर ठेपरा जोंःखस ही तिग्गका उरजिस ती ओरमर तंगअन बछाबअआ उंगियर। मुंज्जा नु आ ठेपरा जोंःखस मून्दा कन्ना ती उढियारनुम बर'उ सोनो गिधिन थिथाबाचस दरा अदिन लवचस की खत्ताचस चिच्चस। इदि खोःखा ओरमर असन जुम्मरर की आ सोनो गिधिन अरा सिम्बाली मन्नन चिच्च तुरु बस्सियर की एडपा किर्यर। नन्ना उल्ला पईरी बाःरी ओरमर तमहँय राःजी किर्यया बअर धरमेस ही नामे ती पुजा—धजा नंज्जर अरा ओण्डर—मोक्खर दरा नलियर बिच्चयर।

अन्तिले ओरमर नन्ना उल्ला पद्दा—खेप्पा अरा अहटा—पहटा तर जुम्मरर की लिटिबीर सिन बेलखा ता बेःल चाःजा गे बिद् ईरयर पहेंस बेद्दा पोल्लर। बअनर लिटिबीरस खोंडहा मजही मल एत्थरस। आस एन्देर केरस का एसते बरचका रहचस अदिन आर बुझुरआ पोल्लर। मुन्दा लिटिबीरस ही तिग्गका एदाचका बेसे 12 चान नु ओंगओल बिसुसेन्दरा ओक्का हेल्लरर। आ धरमी सवंग गही तिग्गका बेसेम पईरी—पुतबारी पचगिर जोंखारिन अरा जोंखर सन्नी कुक्के—कुकेयरिन तेंगा सिखाबआ हेल्लरर। अन्ने सन्नी बेडा तिम सिखिरना अरा सिखाबअना अड्डा दिम धुम ताअ कुड़िया अरा धुम—धुम कुड़िया ती धुमकुड़िया बाताःरा। अवंदा बेडा नु आस कुंडुख खोंडहन दव कुना सइमटाःचस, ससईत ती बछाबाःचस दरा डहरे एःदअर तंगहय राःजी किर्यस केरस। अख'उर बाअनर आस देव आलस तलियस। आःलर ही गोहराःरना ती धरमेस मया ननु देव का मयहदेव (मया ननु देव) ही रूःपे नु आःलर गुसन तईका रहचस। धरमे सवंग आःलारिन एका रूःपे नु मदईत ननी का एका रूःपे नु दिसतार चिअई अदिन ने हुं पोलनर तेंगा। बेडा कट्टी, धरमेस ही लिला

एःदना मुंज्जुर'ई, अदी खोःखा खोंडहा इंजिर'ई का आद धरमे सवंग गही दिम छया—भया रहचा। ई लेखे धरमे सवंग खोंडहन बछाबआ गे अवंदा उल्ला आःलर मझी रअर खोंडहन लूर—घोख चिअर डहरे परपन्द नंज्जा। आ बेडा तिम धरमे सवंग ही तिग्गका अड्डा अरा धरमे सवंग ही धरताःचका घोख बाःरनुम धुम—ताअ कुड़िया अरा धुम—धुम कुड़िया ती धुमकुड़िया बाताःरा। अन्नेम 12 चान नू ओंगओल ई अकलक ती बछरका ही नामे ती सेन्दरा बेःचना दिम बेडा खेपते—खेपते, बसा नना गे सेन्दरा बअनुम बिसुसेन्दरा बाताःरा। अन्ने गा खोंडहा तर तमहँय चिता—बुता ती पहईट गईनका 03 चान नू ओंगओल बिसुसेन्दरा ओक्कनर, पहें पुरखर बआ लगियर का राजी बिसुसेन्दरा 12 चान नू उक्की।

बअनर बिसुसेन्दरा धरमी सवंग गही तिग्गका —सिखाबाचका दिम तली। बिसुसेन्दरा बक्क गही मने एन्ने लेखआ बुझुरतार'ई — बि = बी अरा बिहनी, सु = सुसर ननना। सेन्दरा का अर्थ सोन्दओ ननना अरा रोपडो मनना है। हिन्दी में सेन्दरा का अर्थ लोकहित में किसी अन्यायी का जीवन समाप्ति करना है।

नाम ओरमत तंगआ अयंग—बंगगर गही बी अरा बिहनी तलदत अरा खद्दर तमहँय अयंग—बंगगत गही बी अरा बिहनी तलनर। अवंगे नाम ओरमत गही नलख तली का नमन तंगआ खद्दारिन सुसर नना गे नलख ननोत। अवंगे बाःचका रअई — बी अरा बिहनिन सुसर ननना गे सेन्दरा। ई घोख खोंडहा ता खद्द—खररर गे बरना बेडा ता डहरेन पंगे अरा उजगो कमओ।

संकलन एव आलेख —
डॉ० नारायण उरॉव "सैन्दा"

संयोजक,
अद्दी कुँडुख चाःला धुमकुड़िया पडहा अखडा, रांची,
श्री भउवा उरॉव

झारखण्ड आन्दोलनकारी सेनानी

ग्राम : मदई, था० : चान्हो, जि० : राँची (झारखंड)

8. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल – 2024

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गांव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी-परम्परा के अनुसार "परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा" का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँडुख समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंचों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटक उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंडारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। बिसुसेन्दरा के पहले दिन अर्थात् दिनांक 18 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव के सिर्फ पुरुष लोग गांव-समाज में रूढ़ी व्यवस्था के अन्तर्गत देश के संविधान एवं कानून व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य किये जाने के संबंध में कई पारम्परिक नियमावली को लिखकर संकलन करने पर चर्चा किये। उसके बाद अंतिम दिन अर्थात् दिनांक 19 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव की बैठक में महिलाएँ के साथ शामिल हुईं। महिलाओं द्वारा पूर्व की भांति, लोटा में पानी और आम का डहुरा लेकर पुरुषों का स्वागत की। महिलाओं को यह उम्मीद रहती है कि पुरुष गण अपने परिवार तथा समाज के लिए अच्छा निर्णय करके आये होंगे और गांव समाज को आगे ले जाएंगे। पिछले वर्ष 2023 में बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार महिलाएँ, 9 फुदना वाला 9 पड़हा के लिए, 7 फुदना वाला 7 पड़हा के के लिए तथा 6 फुदना वाला 6 पड़हा गांव के महतो-पहान के लिए अईरपन-सिन्दुर लगाकर "पड़हा खेवा डांग" सौंपा गया और वे पुरुषों से आह्वान कीं – कि वे स्वयं समाज-परिवार के लिए जागें और बच्चों में शिक्षा का अलख जगाएँ, नशापान रोकें, अनुशासन एवं देशप्रेम जगाएँ। इस वर्ष महिलाओं द्वारा फिर से आह्वान किया गया कि गांव के पहान-महतो बिसुसेन्दरा के अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का संकेतक "पड़हा खेवा डांग" को बिसुसेन्दरा में गांव का पड़हा झण्डा के साथ चढ़ावें। इस तरह पुरुष-महिला मिलकर माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान पर आह्वान किये – आदिवासी जागरूक हों।

परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024 की ओर से निम्नांकित निर्णय लिया गया –

1. माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है कि आदिवासी मामले का निपटारा – आदिवासी कस्टमरी कानून के आधार पर हो। इसलिए बिसुसेन्दरा में निर्णय लिया गया कि – उरांव समाज का कोई भी मामला तीन स्तरीय "परम्परागत ग्रामसभा न्याय पंच" व्यवस्था में आना होगा। इनमें से – (क) पददा पंचा अर्थात् ग्राम सभा बैठक करके (ख) पड़हा पंचा अर्थात् पड़हा बैठक करके (ग) बेल पंचा अर्थात् बेल समूह का बैठक करके।

2. पददा पंचा अथवा ग्रामसभा बैठक की अध्यक्षता रूढ़ीगत रूप से गांव के पहान द्वारा किया जाएगा तथा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाए। गांव के कोई मामला ग्राम सभा अध्यक्ष के नाम से लिखित शिकायत आवे और ग्राम सभा अध्यक्ष उस शिकायत के आधार पर दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलावे और गांव के पंच मिलकर न्याय करें। कार्यवाही को ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें और पंच गण हस्ताक्षर करें। इसी तरह पड़हा पंचा की बैठक की अध्यक्षता परम्परागत रूप से पड़हा बेल/बेल पददा के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। पड़हा बेल के मदद के लिए सभी पड़हा गांव वाले रहें। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथा पड़हा बेल एवं पंच गण हस्ताक्षर या अंगुठा लगाएं। तीसरा स्तर – बेल पंचा अथवा पड़हा बेल समूह का बैठक। इस बैठक का अध्यक्षता अपने पड़ोस क्षेत्र के 3 या 5 या 7 पड़हा के पड़हा बेल समूह द्वारा किया जाए, जिसकी अध्यक्षता उन 3 या 5 या 7 में से किसी एक मदईत पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा, जिसका चयन शिकायत कर्ता द्वारा किया जाए। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथथ सभी पड़हा बेल एवं पंच हस्ताक्षर करें या अंगुठा निशान लगाएं।

3. प्रत्येक 03 वर्ष में परम्परागत ग्रामसभा न्याय पंच समिति का गठन करें और इसकी सूचना अपने उपायुक्त महोदय को दें। वर्ष 2024 का "परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल" द्वारा अनुमोदित निर्णय को महामहोम राज्यपाल, झारखण्ड, आयुक्त रांची एवं उपायुक्त गुमला अथवा सचिव डालसा, जिला गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ, भेजें।

ह०/अ० दशरथ भगत प.ग्रा.प.बि.बेल	ह०/अ० जुब्बी उराँव प.ग्रा.प.बि.कुहाबेल	ह०/अ० मटक उरांव प.ग्रा.प.बि.देवान	ह०/अ० गजेन्द्र उरांव, प.ग्रा.प.बि.कोटवार	ह०/अ० श्री उमेश उरांव प.ग्रा.प.बि.भंडारी
--------------------------------------	--	---	--	--

9. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँडुख) समाज की रूढ़ीगत सामाजिक न्याय व्यवस्था
– डॉ नारायण भगत एवं डॉ० नारायण उराँव “सैन्दा”

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी-सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - “We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously.

फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता, रांची

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उराँव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को राँची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. स्वयं ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है.

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है. फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी. कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व

- उराँव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है



कुमार वैभव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि उराँव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था. विवाहेतर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था. **यह है मामला** : उराँव जनजाति के युवक ने राँची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए

याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मेंटेनेबल नहीं है. यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है. कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है. यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

उराँव जनजाति समाज में छूटा-छुटी का है प्रावधान : एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उराँव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छूटा-छुटी) का प्रावधान है. तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी. इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया.

इसी तरह बिलासपुर, छत्तीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – “हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।”

हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

नवभारत रिपोर्टर। विलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए



परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में

याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम हैं। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

‘माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची एवं छत्तीसगढ़ के आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल द्वारा दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से त्रिस्तरीय “परम्परागत ग्राम न्याय पंच” नियमावली 2024 के प्रस्ताव को समीक्षोपरांत अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया।

इसके पूर्व ‘माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विचार-विमर्श कर, त्रिस्तरीय “परम्परागत ग्राम न्याय पंच” – 1. पददा बेजपंचा (ग्रामसभा करके) 2. पड़हा पंचा (पड़हा बैठक करके) 3) बेलपंचा (3 या 5 या 7 पड़हा बेल का बैठक कर) की व्यवस्था को मंजुरी दी गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि परम्परा से चली आ रही बिसुसेन्दरा (परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक विधायिका) में सामाजिक नियम कानून तय किये जाएंगे जो परम्परागत आदिवासी समाज को स्वीकार करना होगा। बिसुसेन्दरा में इस निर्णय के बाद – अब गांव के किसी भी मामले को पहले ग्राम सभा के सामने, लिखित शिकायत करना होगा। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करे और शिकायत का निपटारा करे। ग्राम सभा द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – पड़हा पंचा द्वारा एवं अपील II – बेलपंचा द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बेलपंचा की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा चयनित पड़हा बेल, द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 या 5 या 7 पड़हा बेल में से अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय स्वीकार्य होगा। बेल पंचा हेतु पास-पड़ोस के पड़हा बेल को मदईत अथवा सहयोग के लिए याचिकाकर्ता द्वारा चयनित पड़हा बेल को आमंत्रित किया जाएगा। तीनों बैठक की कार्यवाही में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय का उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ।”

परम्परागत उरांव समाज की त्रिस्तरीय “परम्परागत ग्राम न्याय पंच” प्रणाली को “परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई—भरनो 2023” एवं “परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल 2024 द्वारा लिया गया फैसला प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। उपरोक्त सामाजिक न्याय प्रणाली की पर टिप्पणी न करते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार है :-

1. परम्परागत उरांव समाज में इस व्यवस्था को परम्परागत उरांव समाज नेवई (न्याय) पंच कहा जाए।
2. परम्परागत उरांव समाज नेवई (न्याय) पंच त्रिस्तरीय हो, जिसका स्वरूप इस प्रकार हो -

(क) पददा पंचा (ग्रामसभा करके) - यह ग्राम स्तर पर होता है।

(ख) पड़हा पंचा (पड़हा बैठक करके) - यह उरांव समाज में पड़हा स्तर पर होता है।

(ग) बेल पंचा (बेल समूह का बैठक करके) - कई पड़हा बेल अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 पड़हा बेल, मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार तय होता है।

यहां पददा का अर्थ गांव है। परम्परागत रूप से सभी उरांव गांव में एक अखड़ा है, जहां करम पुजा (पुजा का अर्थ पूरआ गे उःजना समझा जाता है) होता है, एक चाःला थान (सरना स्थल), एक देवीगुड़ी थान (देवी स्थल) और गांव का मसना सामूहिक तौर पर हुआ करता है, परन्तु किसी गांव का टोला में सरना या देवीगुड़ी नहीं होता है। गांव में टोला बढ़ने से देव-पितर का बंटवारा नहीं हुआ है, पर वहां पर चढ़ाए गये जल और फूल का बंटवारा हुआ करता है। वर्तमान समय में खशकर शहरी क्षेत्रों में, इन मुद्दों में भी बदलाव हुआ है। शहर में समाज का समूह छुट गया और समूह छुटने से सामूहिकता और सामूहिक व्यवस्था में विखराव हुआ और उरांव समाज के लोग दूसरे संगठन एवं आस्था-विश्वास वाले समूह के संगत में जाने लगे, जो समाज के लिए अहितकर साबित हुआ।

पंचा का अर्थ उरांव समाज में प्रथागत सामाजिक न्याय प्रणाली से है। इसका संबंध पचा और पचोरा से है जिसे आंशिक तौर पर पंचनामा के अर्थ में समझा जा सकता है। किन्तु हिन्दी में पंचनामा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना है। पर पददा पंचा या पड़हा पंचा या बेल पंचा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना तथा सामाजिक न्याय करना एवं दण्ड विधान निर्धारण करना भी है।

पंचा शब्द के साथ कई गाना उराँव (कुँडुख) भाषा में गाया जाता है -

1. पंचा ननो बाःरी गमय-गोसोय मननय,
पंचा ननो बाःरी गमय-गोसोय मननय।
किस्स अहड़ा मोःख्रो बाःरी लब्ब-लब्ब मननय,
किस्स अहड़ा मोःख्रो बाःरी लब्ब-लब्ब मननय।

भावार्थ - यह गीत महिलाओं द्वारा सामाजिक न्याय के दौरान पुरुषों में उठती भावनाओं पर टिप्पणी है।

2. पंचा भईयर बअदी कोय पेलो,
पंचा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
हेओर दरा लवओर कोय पेलो,
पंचा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
अखड़ा बेःचा बरओन कोय पेलो,
पंचा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।

भावार्थ – एक प्रेमी, अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और उसका साथ के लिए के लिए सज्ज है।

3. बेल झण्डा चोःचा गुचा सपडारआ।
कन्ना-बलम धरआ गुचा बिसुसेन्दरा।
पडहा पंच्वा चोःचा गुचा सपडारआ,
बेल पंच्वा ओक्का गुचा बिसु टोंका।

भावार्थ – यह वीर रस वाली बाल कविता है। बच्चों के बीच इसे सामाजिक जागरण हेतु गाया जाता है।

इस प्रणाली में गांव के किसी शिकायत पर पहले पददा पंच्वा/ग्राम सभा के सामने लाया जाता है। उसके बाद यदि ग्रामसभा के निर्णय पर स्वीकार न होने पर वह मामला पडहा के बीच पहुंचता है और वहां पडहा पंच्वा में गलती पाये जाने पर जुर्माना किया जाता है।

वर्तमान न्यायालय व्यवस्था में किसी मामले को समीक्षा करने के लिए 03 बार अवसर प्रदान किया जाता है। परम्परागत उरांव समाज में भी ग्राम सभा के मामले की समीक्षा प्रथम स्तर पर पडहा में किया जाता है उसके बाद इससे उपरी समीक्षा स्थल बेल पंच्वा के लिए बिसुसेन्दरा द्वारा निर्धारित पंच गण (JURY MEMBER) के माध्यम से समीक्षा किया जाता है। उरांव समाज में इस प्रकार की सामाजिक न्याय प्रणाली एक त्वरित एवं पारदर्शी न्याय प्रणाली है। इस सामाजिक न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता पडने पर परम्परागत ग्रामसभा पडहा बिसुसेन्दरा” में सामाजिक समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है। तीसरे स्तर का बैठक अर्थात बेल पंच्वा के लिए पंच गण (JURY MEMBER) का निर्धारण बिसुसेन्दरा द्वारा तय किया जाता है। बेल पंच्वा के लिए शिकायत आने पर 3 या 5 या 7 पडहा बेल में से आमंत्रित पडहा बेल अपनी टीम के साथ संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं।

इसी संदर्भ में दिनांक 31.05.2022, दिन मंगलवार को डॉ० नारायण उरांव, सैन्दा, सिसई (गुमला), अपने वकील मित्र श्री बिन्देश्वर साहू (वकालत परिसंघ, गुमला) के साथ पारम्परिक उरांव समाज के सामाजिक एवं वैधानिक समस्याओं के संबंध में विमर्श करने हेतु गुमला जिला के डालसा के सचिव महोदय से मिले। डॉ० नारायण उरांव की बातें विधि के जानकारों से हुई। डॉ० नारायण ने सामाजिक मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि – “पारम्परिक एवं रूढ़ीगत व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सामाजिक समस्याएँ कोर्ट-कचहरी में सुनी नहीं जाती है। प्रश्नोत्तर में सचिव महोदय बोले कि कोर्ट या प्राधिकार, शिकायत की सुनवाई करता है, कोई नया नियम नहीं बनाता है। यदि कोई शिकायत हो तो कोर्ट या प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधि सेवा दिया जाएगा और यदि सामाजिक हित में कोई नया नियम बनाने की बात हो तो समाज के लोगों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्यपाल के पास जाना चाहिए। कोर्ट या न्यायालय, संविधान सम्मत तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा एवं न्याय करता है।

उक्त तथ्यों की जानकारी के बाद, परम्परागत पडहा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अपने समाज में हुए शिकायत को बैठकर लिखा-पढी के साथ अभिलेख तैयार करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके लिए, परिवाद यदि परिवार स्तर पर न सुलझे तो रूढ़ी-परम्परा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।

परम्परा के अनुसार वाद या परिवाद को निम्नलिखित तरीके से कार्य किया जाना चाहिए –

1. सर्वप्रथम वाद या विवाद पददा सबहा/ग्राम सभा में आये तो, पददा पंच्वा/ग्रामसभा द्वारा दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष के बातों को गवाहों के सामने सुनकर तथा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गवाह पंचगण होंगे। पददा पंच्वा अथवा ग्रामसभा की अध्यक्षता, रूढ़ी-प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित गांव का पहान द्वारा अथवा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाएगा।

2. यदि पददा पंच्वा/ग्रामसभा में किसी मामले का निपटारा न हो तो यह मामला पडहा में जाएगा। उस पडहा के लोग (जिसमें 3, 5, 7, 9, 12, 22 गांव जो बुनियादि पडहा में एक साथ रहता आया हो) पडहा पंच्वा का बैठक

में निर्णय करें। पड़हा पंचा की अध्यक्षता, पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हो।

3. यदि एक बुनियादि पड़हा स्तर पर मामले का निपटारा न हो तो यह मामला सहयोगी पड़हा (3 या 5 या 7 पड़हा समूह के बेल, अपने सहयोगियों के साथ) बेल पंचा करें और निर्णय लें। बेल पंचा में सबहा की अध्यक्षता, आवेदक द्वारा चयनित पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के सामने लिखित हो। इन तीन बैठक के निर्णय से यदि वादी या प्रतिवादी संतुष्ट न हों तो वे न्यायालय या बिसुसेन्दरा में मामले को ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. भारत देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। परन्तु भारतीय संसद द्वारा 1965 में लोकुर कमिशन का गठन किया गया, जिसका रिपोर्ट अबतक जनजाति मामले में मान्य है। कमिशन की रिपोर्ट में जनजाति के लक्षण बतलाये गए हैं जो इस प्रकार है –

- (क) आदिम लक्षण (जैसे – सेन्दरा, पर्व त्योहार खर्ददी, करम, सोहरई, फग्गु, हरियनी, बेंज्जा आदि।)
- (ख) विशिष्ट संस्कृति (विशिष्ट भाषा एवं विशिष्ट संस्कृति)।
- (ग) भौगोलिक अलगाव (उरॉव छोटानागपुर में, हो कोलहान में, संताल का संतालपरगना में बसाव है।)
- (घ) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच।
- (ङ) पिछड़ापन।

5. परम्परागत आदिवासी समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा एवं विशिष्ट संस्कृति के साथ गुजर-बसर कर रहे हैं। इस दौरान उसे देश की प्रशासनिक एवं न्यायायिक व्यवस्था के साथ सामना करना पड़ता है। इस संबंध में ज्ञात होता है कि देश में दो तरह का कानून है – 1. सिविल लॉ (जो सबके लिए बराबर रूप से सबों पर लागू होता है) 2. सामुदायिक कानून (जैसे – हिन्दु के लिए हिन्दु उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई के लिए भारतीय ईसाई कानून आदि है।)

किन्तु भारत देश में आदिवासी समुदाय के लिए 1997 ई0 से पहले कोई अलग सामुदायिक कानून नहीं बना था। इस संदर्भ में वर्ष 1997 को भूरिया कमिशन बना, जो PESA Act 1997 (पेसा कानून 1997) के रूप में संसद सभा को सौंपा। इसके तहत राज्य सरकार को वहाँ के निवासियों के जनहित में राज्य स्तर पर कानून बनाना है। पेसा एक्ट 1996 की अधिसूचना इस प्रकार है –

THE PROVISION OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996, No. 40 OF 1996
(24th December, 1996)

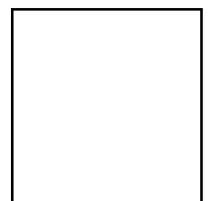
4. (d) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution.

भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(1) में परम्परागत रूढ़ी प्रथा को कानून का बल प्रदान किया गया है तथा पेसा एक्ट 1996, 4(घ) के तहत ग्राम सभा को रूढ़ी प्रथा के अन्तर्गत निराकरण करने का बल प्रदान किया गया है। वैसे न्यायालय में रूढ़ीप्रथा रीति रिवाज के संबंध में निम्न 05 बातें देखी जाती है – 1. प्राचीनता 2. निरंतरता 3. एकरूपता 4. नैतिकता 5. निश्चितता। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए समुदाय में कार्य किया जाए।

आलेख – डॉ नारायण भगत,
विभागाध्यक्ष, कुँडुख विभाग,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।
मो0 न0 – 8521458677



आलेख – डॉ नारायण उरॉव,
संयोजक, अददी कुँडुख चा:ला
धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, राँची
मो0 न0 – 8521458677



10. କୁँडुख भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को बी.ए. एवं एम.ए. के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति से मिला आदिवासी प्रतिनिधि मंडल।



दिनांक – 29 फरबरी 2024 को राँची विश्वविद्यालय, राँची के बी.ए. एवं एम.ए. के कुँडुख भाषा विषय के पाठ्यक्रम में कुँडुख भाषा की लिपि तोलोंग-सिकि को शामिल कराने तथा पठन-पाठन कराने के लिए पारंपरिक स्वशासन पड़हा व्यवस्था गुमला, लोहरदगा, राँची के पड़हा बेल (पड़हा राजा) एवं सदस्यों ने कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची से मुलाकात की। कुलपति महोदय ने अपनी व्यस्तता के बावजूद काफी समय निकाल कर प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। कुलपति महोदय ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के झारखंड आगमन को लेकर उनकी व्यस्तता काफी बढ़ी हुई है। बावजूद इसके कुलपति ने यह आश्वासन दिया कि वह जल्द ही पुनः इस प्रतिनिधिमंडल के साथ 01 मार्च को बातचीत करके मामले का समाधान निकाल लेंगे। हालांकि कुलपति ने प्रतिनिधिमंडल से वह सरकार का गज़ट की कॉपी की मांग की जिसमें कुँडुख तोलोंग-सिकि को राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त है।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा कुलपति को सौंपे गए ज्ञापन में झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, राँची के सचिव, श्री मुख्त्यार सिंह के हस्ताक्षर से गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे गए पत्र में राज्य सरकार की स्वीकृति एवं अनुमति दर्ज है। साथ ही झारखंड इंटरमीडियट काउन्सिल के आदेश पर मैट्रिक परीक्षा में कुँडुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि

लिपि में कराने का निर्देश भी शामिल है। उसके अनुसार 2009 में एक विद्यालय में और 2016 से सभी विद्यालयों में कुँडुख भाषा की परीक्षा तोलोंग सिकि, लिपि में करायी जा रही है।

यहां यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि राँची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में पाठ्यक्रम बनाये जाने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा आदेश दिया गया है। बावजूद इसके जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग ने अब तक कुँडुख भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को शामिल नहीं किया है।

बताते चलें कि झारखंड सहित 29 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों में रहनेवाली जनसंख्या क्रमशः 52 लाख, कुँडुख भाषा-भाषी हैं।

कुलपति से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में रंथु उरावं (12 पड़हा बेल मन्हो जोरी), एतवा उरावं (9 पड़हा करकरी, मंगलो, भरनो, गुमला) जुब्बी उरावं (लोंगा, भरनो), देवस्थन उरावं (7 पड़हा बेल केंद्र वलमी, भंडरा, लोहरदगा) गजेन्द्र उरावं (नौ पड़हा कोटवार सैन्दा), अरविन्द उरावं (नौ पड़हा देवान आताकोरा करकरी, सिसई, भरनो), सुका उरावं (7 पड़हा कोटवार बेड़ो), पंकज उरावं (पहान), विजय उरावं (35 पड़हा बेल लोहरदगा), अजय लकड़ा (12 पड़हा बेड़ो), विनोद भगत (7 पड़हा बाघा लोहरदगा), सुरेश उरावं (7 पड़हा धनकारा लातेहार), संजीव भगत (पारंपरिक स्वशासन पड़हा, लोहरदगा), संतोश उरावं (लातेहार), नरेश उरावं (12 पड़हा सेन्दुर, लोहरदगा), करमा उरावं (12 पड़हा, नरकोपी), डॉ शांति खलखो (शिक्षाविद्), नीतू साक्षी टोप्पो (पेल्लो कोटवार, अद्दी अखड़ा, संस्था, राँची) आदि शामिल हुए।

रिपोर्टर –
गजेन्द्र उरावं
पड़हा कोटवार
परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा
सिसई-भरनो, गुमला
झारखण्ड।

चिआ – एन्ने गुल मेन्दरई। आःलर गही चिचयारना हूँ मेन्दरई। घोड़ो गही चिचयारना हूँ मेन्दरआ लगी। तीन ठो पेल्लर मेत धुती, झुला अत्तरकी मंचे नू कोरनर। आःर गही खेक्खा नू बल्लू धनु-कन्ना (तीर) अरा तड़री रअई। दू झनर ओन्टा मुक्कन सहड़ा चिअर दरा होआ लगनर।)

बल्लू धरचका पेल्लो – लय कोय, इसन कटिक सथारदत ! एःन अम्म बेददेन। (दूइयो मुक्कर, तड़री धरचका लंगड़ऊ आःलिन सहड़ा चिअर की ओकताअनर।)

तड़री धरचका पेल्लो – एकसन हूँ अमके काःला ! एःन कोडेम रअएन।

धनु-कन्ना(तीर) धरचका पेल्लो – बग्गे बड़ियर कत्था अम्बय कच्छनखरअय। एःका पोल्ला लगदी। इंवदा खेंस उर्खिया अरा बआ लगदी एःन कोडेम रअएन। इदिन एःरके तो ! एःन अम्म अरा दवई घाःसी बेददर दरा बरआ लगेन। धनु-कन्ना धरचका पेल्लो मंचे ती चइल काःली।

बल्लू धरचका पेल्लो – बग्गेम नुंज्जआ लगी ?

तड़री धरचका पेल्लो – बग्गे का मला पहेंक खेड्ड थमआ मल चिआ लगी। खेंस एःरर की इलिचका लगगा लगी।

बल्लू धरचका पेल्लो – एःदअय तो खेड्डन, खेड्ड-खोचोल अत्तरा-इत्तरा मंज्जकी रअई होले इदिन ओक्त'एन चि'एन।

तड़री धरचका पेल्लो – मला-मला रआ चि'अयअइयो ... (तंगहय खेड्डन धरई)।

बल्लू धरचका पेल्लो – इंवदा नुंज्जआ लगी अन्नु हूँ मला-मला बअदी। एःदअय खेड्डन ? (जबरई खेड्डन धरई दरा खेड्डन अत्तरा-इत्तरा कप्पी खने लंगड़ऊ आःली चिचयारई।)

तड़री धरचका पेल्लो – अयो अयो अम्बय ची ..हूँ हूँ हूँ ... (कुँहरारई).. मला रअय ची ..आँ...आँ ...।

बल्लू धरचका पेल्लो – छछेम र'अय तो, ओन घड़ी।

(खेड्डन कप्पनूम रई। ओन गुसन कप्पी)

तड़री धरचका पेल्लो –“आँ .. हों ... हों हों हो ... अम्बय ची ... ”

(आ बीरिम बल्लू धरचका पेल्लो खेड्डन नतगी चिई।)

अयो अयो.. एन्देर नंज्जकी .. दःव लगगा लगी.. अयो अयो एंवदा नुंज्जआ लग्गिया।

(बअनुम अलखना बेसेम मनी)

बल्लू धरचका पेल्लो – दःव लग्गिया ?

तड़री धरचका पेल्लो – ह'ई (कुक्कन नुक'ई)।

बल्लू धरचका पेल्लो – सुपली मईन्ता ता ओन्टा खोचोल घसकारकी रहचा .. आःद अक्कु उक्किया। एःन किचरी गने हेएन चिएनकृ पखना गने का एन्देर ती लग्गकी रअदी खेंस उरखा लगी, दःव लग्गो। (गमछा लेखआ किचरिन चरर की अरा भूरियो एःप गने हेअई चिअई)। आ बीरिम धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो खेंता नू अम्म ओन्दोअर की बर'ई।

धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो- सोन खाड़ गा गेच्छम रहचा, हेददेम पझरा रअई असतले केम अम्म ओन्दरआ लगेन। ओनय .. ?

बल्लू धरचका पेल्लो – तुम्मबा रहचका ती एंग्गा हूँ अम्म खक्खरओ पहें।

धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – इदा रई मला। एंगहय गुसन हुरमी रअई। कन्तो हूँ रअई। मोःचना का, खण्डना रअई एन्दरा दिम ?

(कड़मा गुसन हेःचका तुम्मबन कुल्ली दरा अम्म चिअई।)

तड़री धरचका पेल्लो – बबा, कंतो हूँ रअई ? अउर एन्देर एन्देर उइदी तेंगय तो।

धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – बेड़न एःरर की हुरमीन बुझुरना अरा अखना लग्गो। बेस, अनेस एन्देर मना उंग्गी इदिन घोखर की अबड़ा जिनिस-बसुतन समटारकी एडपन ती एकसआ नुम उरुखना चही। एन्देर गही दरकार मना उंग्गी इदिन पेल्लारिन, मुक्कारिन बग्गे बुझुरना लग्गो। एन्नेम गा इंगयो सिखाबाचकी रअई।

बल्लु धरचका पेल्लो – दःव बाःचकी दर्ई। खनेम गा किचरी उइका रहचा एंगहय गुसन। महले इदिही खेड्डन एकासे हेअर की उजगआ ओंगोन पहें।

धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – खनेम गा धनु-कन्ना(तीर), तरवइर, बल्लु, भुरियो गुट्टी चलबआ अखएन। अक्कुन ददा, बबा, कका गर ने हूँ मल्लर होरमर बिसुसेन्दरा केरका रअनर। नमन एन्ने बेड़ा नू ने एःरो, का बछाबओ पहें ? तेंगय तो !

बल्लु धरचका पेल्लो – ई नमहय, सिनगी दर्ई बअय, कइली दर्ई बअय का, चम्पु दर्ईयन बअय। ई होरमा दर्ई गर गा जोखर लेखआ दिम जोरगर, बड़ियर अरा हुसियार रअनर। अन्नेम सेयान हूँ।

तड़री धरचका पेल्लो – खनेम गा तुड़खारिन खेदआ उंग्गकम।

बल्लु धरचका पेल्लो – एःन गा बल्लू गनेम खण्डकन ओरतोसिन।

तड़री धरचका पेल्लो – एःन गा ददस गहि ढंवठा सेन्दरा बिचू का, माक लवउ डण्डन हूँ उंदरकी रहचअन। ओन्टा घोड़ो गही खेड्ड नू एन्ने लेबदाचअन का घोड़ो खत्तरा दिम केरा। इजअम पोल्ला।

धनु-कन्ना(तीर) धरचका पेल्लो – बबा! अन्ने जोरगर नलख नंज्जकी।

बल्लु धरचका पेल्लो – हाँ ! निंगन अक्कु एकासे लग्गा ली। एःका ओंगोय का एन्नेम टंगअर की होअना लग्गो।

तड़री धरचका पेल्लो – एःरेन, (इजअर की एःका बिद्दी, खतरना बेसे मनी, दूयो झनर समढाअनर) धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – सथारओय का जोर ननोय ?

बल्लु धरचका पेल्लो – रहा, (खेड्डन धरई, दूयो झनर अदिन एःरनर।) (मंचे खोंःखा तरा आःलर गही बरना मेन्देरई, घोड़ो बरना लेखआ मेन्देरई।)

धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – मेनय, ओनाबअय तो ने बरआ लगी। सिनगी दर्ई तली का।

बल्लु धरचका पेल्लो – (खेबदा गुसन खेक्खा उय्यरकी ओनाबई, अत्तरा इत्तरा ईकी) अन्नेम गा मेन्देरआ लगी।

धनु-कन्ना (तीर) धरचका मुक्का – हाँ, अन्नेम मेन्देरआ लगी। सिनगी दर्ई दिम तली।

तड़री धरचका पेल्लो – सिनगी दर्ई बरआ लगी।

बल्लु धरचका पेल्लो – हाँ, अन्नेमगा मेन्देरआ लगी। तुड़खारिन अउर ओंगहोन खेदचर बेसे लग्गा लगी।

तड़री धरचका पेल्लो – हअई, अउर ओंगहोन खेदचर पपियहारिन। (इजआ बेद्दी, एंग्गन अतरम होए।

सिनगी दर्ई बरआ लगी।)

धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – हाँ, सिनगी दर्ई दिम हिके।

बल्लु धरचका पेल्लो – गुचे, अतरम कालोत। इदिन घोड़ो नू ओकताअना मनो।

तड़री धरचका पेल्लो – गुचे, आ खोंडहा तरा मेसरओत। गुचे, सिनगी दर्ई बरआ लगी।

धनु-कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – ई मइन धरअय। (दूयो झनर धरनर)

तड़री धरचका पेल्लो – हाँ गुचे, (रीझिरनुम बअई) सिनगी दर्ई बरआ लगी।

दूयो झनर तड़री धरचका पेल्लोन धरनर, चोअर की जोर से एःका हिलिरई – बअनुम काःली, सिनगी दर्ई बरआ लगी, सिनगी दर्ई बरआ लगी।)

12. उराँव समाज प्रतिनिधि मंडल ने तोलोंग सिकि, लिपि के संबंध में राज्यपाल के समक्ष रखी मांग



दिनांक 26.06.2024 दिन बुधवार को 03.00 बजे अपराहन 05 उराँव आदिवासी, अपनी मातृभाषा कुँडुख एवं कुँडुख की लिपि तोलोंग सिकि के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड से मिले प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व सुश्री नीतू साक्षी टोप्पो, पेल्लो कोटवार, अददी अखड़ा, राँची द्वारा किया गया। इस प्रतिनिधि मण्डल में साहित्यकार सह साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के सदस्य श्री महादेव टोप्पो, तोलोंग सिकि लिपि के संस्थापक डा० नारायण उराँव, पड़हा देवान लोहरदगा श्री संजीव भगत, कुँडुख स्कूल मंगलो के प्राधानाचार्य श्री अरविन्द उराँव एवं सुश्री नीतू साक्षी टोप्पो द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

प्रतिनिधि मण्डल ने महामहीम से कहा कि – वे सभी उराँव आदिवासी समूह से हैं। उनकी अर्थात् उराँव समूह की एक विशिष्ट भाषा है जिसका नाम कुँडुख है तथा इस भाषा की अपनी लिपि है जिसका नाम तोलोंग सिकि है। आदिवासी उराँव समाज अपन मातृभाषा एवं लिपि में पढ़ाई लिखाई करना चाहता है। पर सरकार की ओर से इस संबंध में पूरी मदद नहीं मिलती है। ज्ञात हो कि राँची विश्वविद्यालय में 42 वर्ष से हिन्दी-संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी के माध्यम से चल रहा है और अबतक कुँडुख भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि में पढ़ाई-लिखाई आरंभ नहीं हुआ है। इस संदर्भ में समाज द्वारा कई अलग-अलग विभाग में मांग किया जाता रहा है पर विश्वविद्यालय स्तर पर यह सामयिक मांग अबतक अधूरी है। वैसे माध्यमिक स्तर पर कुँडुख कि कुँडुख भाषा की पढ़ाई तोलोंग सिकि लिपि में भी हो। यह मांग माननीय कुलपति राँची विश्वविद्यालय, राँची से प्रतिनिधि मण्डल मिला किन्तु कुलपति महोदय ने कहा कि – लिपि की मान्यता के

संबंध में राजकीय गजट लायें, तभी इसे स्वीकार करेंगे।

ज्ञात हो कि झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने वर्ष 2003 में कुँडुख भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि को स्वीकृति प्रदान किया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद जैक द्वारा कुँडुख भाषा विषय की मैट्रिक परीक्षा तोलोंग सिकि में लिखने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत वर्ष 2009 से एक स्कूल के छात्र तथा वर्ष 2016 से इच्छुक सभी छात्रों के तोलोंग सिकि लिपि में परीक्षा लिखने की अनुमति प्रदान की गई है। परन्तु विश्वविद्यालय स्तर पर अबतक इसकी पढ़ाई-लिखाई नहीं कराया जा रहा है। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इन मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसपर महामहीम राज्यपाल द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया।

महामहीम के साथ परिचर्चा का दूसरा विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ आदिवासी सामाज के बीच धुमकुडिया को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका के स्थान पर जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा होने पर आदिवासी समाज के बच्चे अपनी संस्कृति को बचपन से ही समझेंगे और उसे अमल करेंगे। इसे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों में **Drug addiction** से मुक्ति का रास्ता बनेगा। इस विषय पर भी महामहीम राज्यपाल द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया और इसपर कार्य किए जाने पर सहमति बनी।

चर्चा का तीसरा विषय परम्परागत ग्रामसभा के माध्यम से सामाजिक न्याय व्यवस्था को लागू करना था। इस विषय पर चर्चा हुई कि – अब माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि आदिवासी मामले को उसके कस्टमरी कानून के जरीये निस्पादन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परम्परागत ग्रामसभा-पड़हा को कानूनी मान्यता मिले। इस तरह का कार्य कोलहान क्षेत्र में न्याय पंच कानूनी व्यवस्था झारखण्ड द्वारा लागू कराया जा चुका है। इस विषय पर महामहीम राज्यपाल के माननीय प्रधान सचिव द्वारा कहा गया कि झारखण्ड में पेसा कानून लागू नहीं है, जिसके चलते अनुसूचित क्षेत्र में इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। यह फैसला करना सरकार की जिम्मेदारी है। अंत में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इस विषयों पर महामहीम राज्यपाल के साथ दोबारा आकर मिलने की तैयारी के साथ वहां से सभी प्रतिनिधि मंडल वापस लौट गए।

रिपोर्टर –

नीतू साक्षी टोप्पो पेल्लो कोटवार,
अदी अखड़ा, राँची।

13. राउरकेला, ओड़िसा में धुमकुड़िया विषयक, प्रथम दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न



दिनांक – 29.06.2024 से 30.06.2024 को दो दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के आयोजक – सरना प्रार्थना सभा, उड़ीसा द्वारा सरना चौक निकट धुमकुड़िया भवन, उदितनगर, राउरकेला में आयोजन हुआ। कुंडुख समाज कैसे बचेगी ? इसी सवाल का जवाब में – विलुप्त होती अपनी मातृभाषा कुंडुख, पड़हा, धुमकुड़िया, अखड़ा, सारना (अध्यात्म स्त्रोत – सरना प्रार्थना सभा) सरना धरम, नेःगचार, कुंडुख संस्कृति आदि का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए उरांव कुंडुख समुदाय क्या कर रही है ? इसे जानने समझने की आवश्यकता है। डॉ. नारायण उराँव, तोलोंग सिकि आविष्कारक एवं अरविंद उराँव, संस्थापक – कुंडुख स्कूल, मंगलो के बीच उड़ीसा राज्य के कुंडुख उराँव समुदाय की अपनी भाषा लिपि पर उनकी स्थिति के बारे में चर्चा किया करते थे। डॉ. उराँव हमेशा कहते थे कि झारखंड से बेहतर पड़हा व्यवस्था का संचालन उड़ीसा के कुंडुख कर रहे हैं। लेकिन अपनी भाषा-लिपि एवं धुमकुड़िया पर स्पष्ट निर्णय का पता नहीं चलता है। उड़ीसा वाले आगे क्या निर्णय लेते हैं। इससे आगे बात नहीं बढ़ पाती थी। धुमकुड़िया 2024 राउरकेला, उड़ीसा में शामिल होने के बाद एक नया उम्मीद, तोलोंग खोड़हा, झारखंड में जाग उठी है। अब उड़ीसा के कुंडुख उराँव समुदाय सही निर्णय लेते हुए अपनी विलुप्त होती कुंडुख भाषा को बचाने एवं कुंडुख भाषा की अपनी लिपि तोलोंग सिकि को उड़ीसा सरकार से मान्यता लेने हेतु आवेदन करने की उम्मीद है। झारखंड से मैं अरविन्द उराँव, नीतु साक्षी टोप्पो, श्री भुवनेश्वर उराँव तीनों धुमकुड़िया 2024, राउरकेला उड़ीसा में शामिल होकर अपने समुदाय को बचा पाने का अनुभव महसूस कर रहे

हैं। धुमकुड़िया में इतने पेल्लर-जोंखर का शामिल होना एक अच्छा संकेत है। इससे पहले झारखंड के सिसई, टुकू सैन्दा नामक स्थान पर धुमकुड़िया शिक्षण शुरू करने के लिए लगभग 250, इंटर, बी. ए., एम.ए. के कुंडुख पेल्लर-जोंखर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2020 में शामिल हुए थे। परिणाम स्वरूप खास कर झारखंड के गुमला, लोहरदगा, रांची जिला में धुमकुड़िया शिक्षण कार्य प्रारंभ की जा रही है।

डॉ. नारायण उराँव ने कुंडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि पर 30 वर्षों का कार्य उपलब्धि को साझा किया एवं धुमकुड़िया 2024, उड़ीसा, राउरकेला में शामिल पेल्लर-जोंखर को अनेक समाजिक गुर सिखाये। सरना प्रार्थना सभा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रवि तिग्गा जी ने धुमकुड़िया 2024 राउरकेला शामिल पेल्लर-जोंखर को अपनी सरना धरम, संस्कृति के बारे में विस्तार से बताये। आयोजन कर्ता मणीलाल केरकेट्टा, राउरकेला, उड़ीसा के विचारधारा पर कुंडुख समाज को चलने की आवश्यकता है। श्री मणिलाल केरकेट्टा जी के धरम पत्नी ने डॉ. नारायण उराँव के बातों को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद बताई कि शुरू में खटपट सा लगा लेकिन बाद में बहुत ही अच्छी-अच्छी बातों को बता रहे थे जो सुनने योग्य था और उनकी बातों को अमल करने की जरूरत है। और उनके बताये मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित युवा उत्साहित होकर वक्ताओं को सुन रहे थे। तोलोंग सिकि वर्णमाला को लेकर उन्होंने डॉ. नारायण उराँव श्रैंदाश से कई सवाल भी पूछे जैसे अंग्रेजी में पांच स्वरों से अलग तोलोंग सिकि लिपि में छह स्वर क्यों हैं? भाषा लिपि समझने के लिए उन्हें रोचक संतोश जनक जवाब मिला।

झारखंड सरकार में तोलोंग सिकि का मान्यता –

कुंडुख भाषा को बचाने का संकल्प हम सभी कुंडुख को लेना ही होगा। अन्यथा पूर्वजों और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। डॉ. नारायण उराँव, तोलोंग सिकि जन्मदाता, पेशे से डॉक्टर होते हुए अपनी मातृभाषा कुंडुख एवं कुंडुख समाज को बचाने के लिए दिन-रात

कार्य कर रहे हैं। उनके 30 वर्षों का तोलोंग सिकि पर कार्य को फलते-फूलते देख सकते हैं। 5/6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 9 पढ़ा (3 संगी पढ़ा, 22 पढ़ा) सिसई भरनो के द्वारा आयोजित शिवनाथ-चटकपुर बगीचा में पहला बिसुसेन्दरा 2011 में डॉ० उराँव के द्वारा सेन्दरा सभा को संबोधित करते हुए कुँडुख प्रवेशिका पुस्तक "कइलगा" को कुँडुख समाज सिसई, भरनो के बीच पहली बार प्रस्तुत किये थे। उसी सेन्दरा सभा में मैं अरविंद उराँव, कार्तिक उराँव आदिवासी कुँडुख स्कूल मंगलो, सिसई, गुमला (झारखंड) के माध्यम से विलुप्त होती अपनी मातृभाषा कुँडुख एवं संस्कृति को बचाने का छोटी सी प्रयास को साझा, डॉ० उराँव की उपस्थित में किया था। उसने मुझसे एक ही सवाल किये थे। नीन नन्नर घी गोहलन एँवदां उल्ला उयोय ? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं थु, लेकिन उसने बिसुसेन्दरा में उपस्थित कुँडुखर के बीच इस सवाल का जवाब चाहते थे। इसलिए कहा बुझुरकय ? हमने कहा हाँ, यदि उसी समय डॉ० उराँव के द्वारा दूसरा सवाल एंदरा बुझुरकय ? करते तो, पता नहीं मेरा स्थिति क्या होता ? बिसुसेन्दरा से वापसी के दौरान उत्तर ढूँढ लिया। घर पहुंच कर तीन घंटे में तोलोंग सिकि से लिखना-पढ़ना-सीखा और ठीक उसके अगले दिन से ही विद्यालय में कुँडुख भाषा विषय को उनकी लिपि तोलोंग सिकि से पढ़ाना-लिखाना शुरू की गई। 2012 से लगातार कुँडुख स्कूल मंगलो के छात्र, छात्राओं के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा एक भाषा विषय कुँडुख को उनकी लिपि तोलोंग सिकि से लिखने के लिए अनुमति झारखंड सरकार से वर्ष 2016 तक की गई। अंततः 12 फरवरी 2016 को तोलोंग सिकि से मैट्रिक की परीक्षा एक भाषा विषय कुँडुख को लिखने की अनुमति झारखंड सरकार के द्वारा दी गई। यह मांग हेतु अनेक कुँडुख लूरगर, बुद्धिजीवी लोग आगे आए इसका परिणाम है। कुँडुख समाज का यह पहला उपलब्ध था इस तिथि को अस्थाई बृहत कुँडुख तोलोंग जतरा का आयोजन झारखंड में की जाती रही है।

बंगाल सरकार ने वर्ष 2018 में तोलोंग सिकि को मान्यता दी -

आप सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए लिपि की आवश्यकता

होती है। तभी उन भाषा का पूर्ण विकास किया जा सकता है।

कुँडुख/उराँव समुदाय (उड़ीसा), जल्द तोलोंग सिकि को उड़ीसा सरकार से मान्यता हेतु आवेदन करेगी। बुदु केरकेट्टा, कोषाध्यक्ष, सरना प्रार्थना सभा स्टेट कमिटी, उड़ीसा ने बताया कि कुँडुख भाषा की अपनी लिपि तोलोंग सिकि को उड़ीसा सरकार से मान्यता हेतु तैयारी की जा रही है।



धुमकुड़िया 2024 राउरकेला मे 220 पेल्लर-जोखर शामिल हुए यदि कुँडुख समाज का विकास के लिए युवक-युवतियों को धुमकुड़िया के माध्यम से प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। वहां मौजूद सरना स्थल 7 एकड़ पर फैला हुआ है यह भारत का सबसे बड़ा सरना स्थल का रिकॉर्ड होगा जो एक शहर के बीच में है। उड़ीसा कुँडुख समुदाय (सरना प्रार्थना सभा) का इस अहम योगदान याद रखने योग्य है। धुमकुड़िया 2024 राउरकेला का सफल आयोजन में निम्न सरना प्रार्थना सभा के पद धारियों का मुख्य योगदान रहा।

सरना प्रार्थना सभा स्टेट कमिटी -

अध्यक्ष - मणीलाल केरकेट्टा

उपाध्यक्ष - गजेन्द्र गिद्ध

सचिव - सुशील कुमार लकड़ा

संयुक्त सचिव - धनेशवर तिकी

कोषाध्यक्ष - बुदु केरकेट्टा

सरना प्रार्थना सभा जिला कमिटी के

अध्यक्ष - बिल्लु तिकी

उपाध्यक्ष - सशील खलखो (फाइनेंशियल मैनेजमेंट)

सचिव - अननता उराँव

(रिपोर्ट : अरविन्द उराँव, कुँडुख स्कूल, मंगलो, सिसई)

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी (टी०सी०एस०)

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी, टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हाशिये पर आ चुके सामुदायों विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ही कार्यरत इकाई है। यह एक अव्यवसायिक और स्वयंसेवी संगठन है। ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी की यात्रा 1974 में तब शुरू हुई जबकी इसने जनजातीय मामलों के लिए एक संयुक्त समिति के रूप में कार्य करना प्ररंभ किया। वर्ष 1993 में समिति पंजीयन अधिनियम के तहत इसका एक समिति के रूप में पंजीयन कराया गया। टाटा स्टील ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी का मुख्य उद्देश्य जनजाति अस्मिता और धरोहर को प्रोत्साहित करना है। यह जनजातीय जीवन, संस्कृति तथा अजीविका के विभिन्न पक्षों में आर्थिक पहल के जरिए जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से सम्बद्ध गतिविधियों पर केंद्रित है। कार्य के प्रमुख क्षेत्र हैं :-

- ❖ जनजातीय समुदायों की देशज अस्मिता या मौलिक पहचान का संरक्षण और संवर्धन।
- ❖ सशक्त समाजों के निर्माण हेतु शिक्षा को विशेषतः युवाओं के मध्य प्रोत्साहित करना।
- ❖ कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।

